

# अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावनाएं

# 1

## अध्याय

संवृद्धि प्रबंधन और मूल्य स्थिरता बृहत् आर्थिक नीति निर्माण की प्रमुख चुनौतियां हैं। वर्ष 2011-12 में भारत ने स्वयं को इन संघर्षकारी मांगों में पूर्णतया उलझा हुआ पाया। विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 8.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल करने के पश्चात, वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की संवृद्धि होने की आशा है। यह न केवल पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में बल्कि 2003 से 2011 की अवधि (सिवाए 2008-09 के) की तुलना में भी अवमंदन निर्दिष्ट करती है। इसके साथ ही, इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि किसी भी अन्य देश से तुलना करने पर भारत एक अग्रणी ही रहा है। कृषि तथा सेवाओं का निष्पादन अच्छा होते हुए भारत का अवमंदन लगभग सम्पूर्णतः कमजोर होती औद्योगिक वृद्धि पर आरोपित किया जा सकता है। वर्ष 2011-12 की दूसरी तथा तीसरी तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र में 2.7 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा यथा मापित मुद्रास्फीति मौजूदा राजकोषीय वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान उच्च थी यद्यपि वर्षांत में इसमें सुस्पष्ट अवमंदन आया है। खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से कम होकर लगभग शून्य हो गई है तथा अधिकांश शेष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति खाद्य भिन्न विनिर्माणकारी उत्पादों द्वारा अभिप्रेरित है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर रोक लगाने के लिए वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की स्थिति पर अंकुश लगाया गया। मंद होती मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के अवशिष्ट प्रभावों को प्रतिबिम्बित करती है। कमजोर विनिर्माण क्रियाकलाप तथा बढ़ती लागतों को प्रतिबिम्बित करते हुए, केन्द्र के राजस्व प्रत्याशित राजस्व से कम रहे हैं तथा बजट में व्यवस्था किए गए व्यय से उच्चतर व्यय के साथ राजकोषीय पक्ष पर कमी होने की आशा है। वैश्विक आर्थिक माहौल, जो वर्ष भर साधारण रहा है, यूरोजोन में उथल पुथल तथा दर निधारण अभिकरणों द्वारा अमरीकी अर्थव्यवस्था संबंधी संभावनाओं के बारे में उठाए गए प्रश्नों के कारण सितम्बर 2011 में प्रखरता से प्रतिकूल हो गया। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इस संयोजन पर संवृद्धि और स्थिरता की संभावना अधिक आशाजनक प्रतीत होती है। कुछ उच्च प्रायिकता संकेतकों से यह संकेत मिले हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप में कमजोरी निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है तथा एक क्रमिक उत्थान अवश्यभावी है।

1.2 आर्थिक समीक्षा 2010-11 के प्रस्तुतीकरण के समय फरवरी 2011 में वृहद् आर्थिक स्थिति धनात्मक प्रतीत हो रही थी यद्यपि औद्योगिक मंदी के बारे में कुछ चिंताएं विद्यमान थी। आर्थिक समीक्षा 2010-11 में यह प्रत्याशा की गई थी कि वर्ष 2011-12 में लगभग 9 प्रतिशत (+ या -0.25 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2005-06 से 2007-08 की तीन वर्षीय अवधि के दौरान हासिल पूर्व संकट स्तरों पर प्रतिवर्तित हो जाएगी। यह आशावाद अंशतः इस तथ्य द्वारा अभिप्रेरित था कि अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11

के दौरान 8.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल की थी तथा बचत एवं निवेश दरों का एक बार पुनः बढ़ना आरम्भ हो गया था। तथापि, वर्ष के दौरान वर्धनात्मक रूप से यह स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था की इस संवृद्धि दर में विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण कमी रहेगी। यह वस्तुतः वर्ष 2011-12 के लिए मध्य-वर्षीय विश्लेषण में निर्दिष्ट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा वर्ष के दौरान 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की आशा है। जैसा कि हुआ है, 7 फरवरी, 2012 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार

0.1 मुख्य संकेतक

आंकड़ा श्रेणियां और संघटक	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>1. स.घ.उ. और संबंधित संकेतक</b>							
स.घ.उ. (वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ करोड़	4294706	4987090	5630063	6457352 <sup>अ.अ.</sup>	7674148 <sup>त्व.अ.</sup>	8912178 <sup>अ.अ.</sup>
वृद्धि दर	%	16.3	16.1	12.9	14.7	18.8	16.1
स.घ.उ. (घटक लागत 2004-05 के मूल्य पर)	₹ करोड़	3564364	3896636	4158676	4507637 <sup>अ.अ.</sup>	4885954 <sup>त्व.अ.</sup>	5222027 <sup>अ.अ.</sup>
वृद्धि दर	%	9.6	9.3	6.7	8.4	8.4	6.9
बचत दर	स.घ.उ. का %	34.6	36.8	32.0	33.8	32.3	उ.न.
पूँजी निर्माण (दर)	स.घ.उ. का %	35.7	38.1	34.3	36.6	35.1	उ.न.
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर उपादान लागत)	₹	31206	35825	40775	46117	53331	60972
<b>2. उत्पादन</b>							
खाद्यान्न	मिलियन टन	217.3	230.8	234.5	218.1	244.8	250.4 <sup>क</sup>
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक <sup>ख</sup> (वृद्धि)	प्रतिशत	12.9	15.5	2.5	5.3	8.2	3.6 <sup>ग</sup>
विद्युत उत्पादन (वृद्धि)	प्रतिशत	7.3	6.3	2.7	6.1	5.5	9.4 <sup>ग</sup>
<b>3. कीमतें</b>							
मुद्रास्फीति (शो.मू.सू.) (52 माह औसत)	% परिवर्तन	6.6	4.7	8.1	3.8	9.6	9.1 <sup>घ</sup>
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू) (औसत)	% परिवर्तन	6.7	6.2	9.1	12.4	10.4	8.4 <sup>घ</sup>
<b>4. वैदेशिक क्षेत्र</b>							
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	22.6	29.0	13.6	-3.5	40.5	23.5 <sup>घ</sup>
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	24.5	35.5	20.7	-5.0	28.2	29.4 <sup>घ</sup>
चालू खाता घाटा (सीएबी)/स.घ.उ.	प्रतिशत	-1.0	-1.3	-2.3	-2.8	-2.7	-3.6 <sup>घ</sup>
विदेशी मुद्रा भण्डार	बिलियन अमरीकी डालर	199.2	309.7	252.0	279.1	304.8	292.8 <sup>घ</sup>
औसत विनिमय दर	₹/अमरीकी डालर	45.25	40.26	45.99	47.44	45.56	47.70 <sup>घ</sup>
<b>5. मुद्रा तथा ऋण</b>							
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	21.3	21.4	19.3	16.8	16.0	14.4 <sup>घ</sup>
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	16.4 <sup>घ</sup>
<b>6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)</b>							
सकल राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. का %	3.3	2.5	6.0	6.5	4.8 <sup>घ</sup>	4.6 <sup>घ</sup>
राजस्व घाटा	स.घ.उ. का %	1.9	1.1	4.5	5.2	3.2 <sup>घ</sup>	3.4 <sup>घ</sup>
प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. का %	-0.2	-0.9	2.6	3.2	1.8 <sup>घ</sup>	1.6 <sup>घ</sup>
<b>7. जनसंख्या</b>							
	मिलियन	1122	1138	1154	1170	1210 <sup>घ</sup>	उ.न.

अ.अ वर्ष 2011-12 के लिए स.घ.उ. आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं; त्व.अ. त्वरित अनुमान अन.अ. अनंतिम अनुमान उन उपलब्ध नहीं/

क द्वितीय अग्रिम अनुमान

ख औद्योगिक उत्पादन संबंधी सूचकांक के आधार (2004-05= 10) पर 2005-06 से संशोधित किया गया है।

ग अप्रैल-दिसम्बर 2011

घ अप्रैल 2011 दिसम्बर 2012

ङ 2011-12 के लिए स.घ.उ. अनुपात की तुलना में सीएबी अप्रैल-सितंबर, 2011 की अवधि के लिए है।

च जनवरी अंत 2012 के अनुसार

छ 2011-12 के लिए औसत विनिमय दर (अप्रैल 2011-फरवरी 2012)

ज अनंतिम (27 जनवरी, 2012 तक)

झ 2010-11 के लिए राजकोषीय संकेतक अनंतिम वास्तविक आंकड़ों के अनुसार हैं।

ञ बजट अनुमान

ट जनगणना 2011

वर्ष 2011-12 में अर्थव्यवस्था द्वारा 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने की आशा है। क्षेत्रक स्तर पर, संवृद्धि के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2.5 प्रतिशत होने का अनुमान है जो प्रत्याशित वृद्धि से थोड़ी सी कम है। तथापि, इसे वर्ष 2010-11 में हासिल 7 प्रतिशत की वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना है। सेवा क्षेत्र में संवृद्धि वर्ष 2010-11 में 9.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में लगभग 9.4 प्रतिशत होने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में उद्योग की वृद्धि के कम होकर 3.9 प्रतिशत होना ही वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अवमंदन में परिणामी हुआ है। (सारणी 1.1)

1.3 वर्ष 2008-09 को छोड़कर जब संवृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी, वर्ष 2011-12 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नौ वर्षों में से निम्नतम वृद्धि रही है। यह पिछले नौ वर्षों की अच्छी स्थिति का संकेतक है किन्तु इसे एक चेतावनी भी माना जाना चाहिए। वर्ष 2008-09 की भांति, मंदी का एक आंशिक कारण वैश्विक कारकों में सन्निहित है जिनमें से विशेष कारण हैं यूरो जोन क्षेत्र में संकट तथा यूरोप में प्रवृत्त लगभग अवमंदनकारी स्थितियां; संयुक्त राज्य अमरीका जैसे कई अन्य औद्योगिकीकृत देशों में धीमी वृद्धि; जापान में प्रगतिरोध; तथा कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जिनका भारत पर सदैव अत्यधिक प्रभाव पड़ता रहा है। घरेलू कारक नामतः मौद्रिक नीति का कठोर होना, विशेष रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को समर्थित करने के उद्देश्य से रीपो दर को बढ़ाना विशेषतया औद्योगिक क्षेत्र में निवेश तथा संवृद्धि में कुछ अवमंदन में परिणामी हुए हैं। चूंकि मौद्रिक नीति अधिकांशतः अल्पावधि में मांग संपीड़न के जरिए प्रचालन करती है, प्रत्याशा यह है कि यह नीति वस्तुतः दीर्घावधिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। वर्ष 2008-09 में भारत में तब अवमंदन आया जब देश के राजकोषीय अधिशेष मजबूत थे। अतः राजकोषीय तथा मौद्रिक प्रेरण के लिए पर्याप्त गुंजायश थी। विश्व के अधिकांश भागों में प्रवृत्त स्थिति की भांति, यह दूसरा

अवमंदन पिछले अवमंदन के पश्चात इतनी शीघ्रता से आ रहा है कि राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति के अर्थ में हमारे पास विद्यमान गुंजायश कहीं अधिक सीमित है। स्पष्टतया, नीति के अर्थ में नवाचारी होने की आवश्यकता है।

1.4 पूर्ववर्ती आर्थिक समीक्षाओं ने सकल घरेलू उत्पाद के दो मापों के बीच बढ़ते अंतर पर विशिष्ट प्रकाश डाला था नामतः सतत् कीमतों पर घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि) तथा सतत् बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (मांग पक्ष सकल घरेलू उत्पाद) जो वैश्विक वित्तीय संकट तथा नीतिगत अनुक्रियाओं से प्रत्युत्पन्न हुआ था जिसमें राजकोषीय प्रेरण शामिल था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 31 जनवरी 2012 को जारी राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों द्वारा घोषित सकल घरेलू उत्पाद में नवीनतम संशोधनों के अनुसार, मांग पक्ष सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2008-09 में हुई वृद्धि के केवल 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है तथा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में सुधार क्रमशः 8.2 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत पर तीव्रतर था (सारणी 1.2)। संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि वर्ष 2008-09 में वैश्विक संकट मुख्यतः सकल पूंजी निर्माण में ऋणात्मक वृद्धि में प्रतिबिम्बित हुआ जब निजी अंतिम उपभोग व्यय में मंदी मामूली सी थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सकल नियत पूंजी निर्माण में संकट पश्च वृद्धि अत्यंत धीमी रही है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार बाजार कीमतों पर संघ-उ० की वृद्धि 7.5 प्रतिशत होने की आशा है। खपत व्यय, सकल नियत पूंजी निर्माण, निर्यातों तथा आयातों की वास्तविक अर्थ में वृद्धि वर्ष 2011-12 के लिए क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत, 14.3 प्रतिशत तथा 17.5 प्रतिशत परिकल्पित होती है। वर्ष 2010-11 में इन संकेतकों में वृद्धि क्रमशः 8.1 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 22.7 प्रतिशत तथा 15.6 प्रतिशत थी। वास्तविक अर्थों में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि की दर काफी सुसंगत रही है तथा वृद्धि दर के सापेक्षतया निम्नतर होने के समय भी इस में महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई जिसका कारण

सारणी 1.1 : 2004-2005 कीमतों पर घटक लागत पर स.घ.उ. में वृद्धि ( प्रतिशत )

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 अन.अ.	2010-11 त्व.अ.	2011-12 अ.अ.
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	5.1	4.2	5.8	0.1	1.0	7.0	2.5
खनन तथा उत्खनन	1.3	7.5	3.7	2.1	6.3	5.0	-2.2
विनिर्माण	10.1	14.3	10.3	4.3	9.7	7.6	3.9
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	7.1	9.3	8.3	4.6	6.3	3.0	8.3
संरचना	12.8	10.3	10.8	5.3	7.0	8.0	4.8
व्यापार, होटल, परिवहन, तथा संचार	12.1	11.7	10.7	7.6	10.3	11.1	11.2
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	12.6	14.0	12.0	12.0	9.4	10.4	9.1
समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	7.1	2.8	6.9	12.5	12.0	4.5	5.9
<b>घटक लागत पर संघ-उ०</b>	<b>9.5</b>	<b>9.6</b>	<b>9.3</b>	<b>6.7</b>	<b>8.4</b>	<b>8.4</b>	<b>6.9</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

टिप्पणी: अन.अ.: अनंतिम अनुमान, त्व.अ.: त्वरित अनुमान

अ.अ. अग्रिम अनुमान

## सारणी 1.2 : सतत् बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि ( प्रतिशत )

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 <sup>अन.अ.</sup>	2010-11 <sup>त्व.अ.</sup>	2011-12 <sup>अ.अ.</sup>
1. कुल अंतिम उपभोग व्यय	8.7	7.7	9.4	7.7	8.3	8.1	6.0
1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय	8.6	8.5	9.4	7.2	7.2	8.1	6.5
1.2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	8.9	3.8	9.6	10.4	14.3	7.8	3.9
2. सकल पूंजी निर्माण	16.3	15.3	17.2	-1.6	11.6	11.1	5.8
2.1 सकल नियत पूंजी निर्माण	16.2	13.8	16.2	3.5	6.8	7.5	5.6
2.2 स्टॉक में परिवर्तन	26.7	31.6	31.3	-51.4	63.2	37.4	2.9
2.3 मूल्यवान वस्तुएं	-1.6	13.7	2.9	26.9	57.6	32.4	12.5
3. निर्यात	26.1	20.4	5.9	14.6	-4.8	22.7	14.3
4. घटाएं आयात	32.6	21.5	10.2	22.7	-2.2	15.6	17.5
5. विसंगतियां	48.2	47.5	111.8	-75.3	230.5	38.9	-111.6
2004-05 बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि	9.3	9.3	9.8	3.9	8.2	9.6	7.5

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

अंशतः निजी खपत का अंतर्हित स्वरूप था जिसमें अन्य मांग पक्ष संघटकों के समान अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता तथा अंशतः मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियां थीं जो अर्थव्यवस्था में खपत के स्तर को प्रभावित करने के बजाए बचतों को कम करने (ब्याज दरों में अपचयन के कारण) की ओर प्रवृत्त है।

1.5 अर्थव्यवस्था में निवेश की संवृद्धि दर में वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। इस वर्ष ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है जो उधारों की उच्चतर लागतों में परिणामी हुई है; तथा अन्य बढ़ती लागतों ने लाभप्रदता को प्रभावित किया है तथा इस प्रकार आंतरिक उपार्जन प्रभावित हुए हैं जिनका प्रयोग निवेश का वित्तपोषण करने के लिए किया जा सकता था। सारणी 1.2 से यह भी अवलोकित किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था ने 2005-06 से 2007-08 के दौरान सकल पूंजी निर्माण में उच्च वृद्धि दर्ज की। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में निवेश दर में तीव्र वृद्धि हुई थी जो वर्ष 2004-05 में 32.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 38.1 प्रतिशत हो गई थी (सारणी 1.4)। निवेश के स्तर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन के पश्चात 2008-09 में निरपेक्ष अर्थों में गिरावट आई। यद्यपि वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में इसमें तीव्रता से सुधार हो गया, सकल पूंजी-निर्माण में, विशेषतया नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि वर्ष 2005-06 से 2007-08 में हासिल वृद्धि की अपेक्षा काफी कम रही है। निवेश दर वर्ष 2007-08 में हासिल किए गए चरम स्तर से अपेक्षाकृत निम्न बनी हुई है।

1.6 वैश्विक अर्थव्यवस्था में कठिन परिस्थितियों के बावजूद मौजूदा वर्ष में निर्यात मजबूत बने रहे और उन्होंने पिछले वर्ष (2010-11) में हासिल 22.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वास्तविक अर्थों में उससे 14.3 प्रतिशत की अधिक वृद्धि दर दर्ज

की। आयातों का 2010-11 में 15.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष के अंत तक 17.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर तक पहुंचना संभावित है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लेखों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आयात और निर्यात) 2004-05 में 37 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर अब सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 53 प्रतिशत है।

1.7 जैसाकि पैरा 1.4 में कहा गया है निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर तब भी काफी संगत बनी रही, जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव आया है। तथापि, यह सुसंगतता विभिन्न जिस समूहों के बीच विशाल विविधताओं को आवृत्त करती है, जैसाकि सारणी 1.3 से देखा जा सकता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय जो 2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान 7.1-9.2 प्रतिशत की श्रेणी में था, में समग्र वृद्धि की तुलना में, खाद्य, पदार्थों, पेय पदार्थों और तंबाकू तथा सकल किराया, ईंधन और विद्युत के उपभोग समूहों की वृद्धि दरें सामान्यतया निम्नतर रही हैं। दूसरी ओर, फर्नीचर और फर्निशिंग, परिवहन और संचार जैसी मदों तथा प्रकीर्ण वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि दरें सामान्यतया उच्चतर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, हिस्सों के संदर्भ में, निजी अंतिम उपभोग व्यय के संयोजन में परिवर्तन हुए, जैसाकि सारणी 1.3 में दर्शाया गया है।

## बचतें और निवेश

1.8 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतें (बचत दर) 2009-10 में 33.8 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 32.3 प्रतिशत हो गयीं। (सारणी 1.4)। यह गिरावट निजी बचतों मुख्यतया वित्तीय परिसंपत्तियों में

सारणी 1.3 : निजी अंतिम उपभोग व्यय : 2004-05 कीमतों पर वार्षिक संवृद्धि और हिस्से							
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 <sup>अन.अ.</sup>	2010-11 <sup>त्व.अ.</sup>
	<b>वार्षिक वृद्धि ( प्रतिशत )</b>						
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू		6.3	3.4	6.4	3.3	0.3	6.2
कपड़े और जूते		19.7	23.3	5.0	5.0	14.9	3.6
सकल किराया, ईंधन और बिजली		3.7	3.8	4.7	3.6	5.4	4.9
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि		15.1	17.1	16.1	12.2	8.7	13.0
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं		8.8	8.7	4.5	6.9	8.9	7.6
परिवहन और संचार		5.8	9.1	7.9	7.7	12.0	12.5
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं		11.0	8.4	9.8	6.8	4.0	5.6
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं		20.1	21.1	28.6	20.2	15.7	11.4
<b>जोड़ निजी उपभोग</b>		<b>8.5</b>	<b>8.7</b>	<b>9.2</b>	<b>7.1</b>	<b>7.4</b>	<b>8.2</b>
	<b>योग में हिस्सा ( प्रतिशत )</b>						
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू	40.0	39.1	37.3	36.3	35.0	32.7	32.1
कपड़े और जूते	6.6	7.3	8.3	8.0	7.8	8.4	8.0
सकल किराया, ईंधन और बिजली	13.8	13.2	12.6	12.1	11.7	11.5	11.1
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8
परिवहन और संचार	19.3	18.8	18.9	18.7	18.8	19.6	20.4
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं	8.9	9.9	11.0	13.0	14.6	15.7	16.2
<b>जोड़ निजी उपभोग</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

पारिवारिक बचतों में कमी के कारण हुई थी, और इसका थोड़ा-बहुत श्रेय कारपोरेट बचतों में कमी को जाता है। दूसरी ओर,

राजकोषीय समेकन की बदौलत, सरकारी बचतों में वृद्धि दर्ज की गई। परिवारों की वित्तीय बचत दर में कमी का आंशिक श्रेय इस

सारणी 1.4 : स.घ.उ. की तुलना में बचतों और निवेश का अनुपात ( चालू बाजार कीमतों पर प्रतिशत )							
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 <sup>अन.अ.</sup>	2010-11 <sup>त्व.अ.</sup>
<b>सकल घरेलू बचतें</b>	<b>32.4</b>	<b>33.4</b>	<b>34.6</b>	<b>36.8</b>	<b>32.0</b>	<b>33.8</b>	<b>32.3</b>
सरकारी क्षेत्र	2.3	2.4	3.6	5.0	1.0	0.2	1.7
निजी क्षेत्र	30.1	31.0	31.0	31.8	31.1	33.6	30.6
पारिवारिक क्षेत्र	23.6	23.5	23.2	22.4	23.6	25.4	22.8
वित्तीय बचत	10.1	11.9	11.3	11.6	10.1	12.9	10.0
भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	13.4	11.7	11.9	10.8	13.5	12.4	12.8
निजी कारपोरेट क्षेत्र	6.6	7.5	7.9	9.4	7.4	8.2	7.9
<b>सकल पूंजी निर्माण ( निवेश )</b>	<b>32.8</b>	<b>34.7</b>	<b>35.7</b>	<b>38.1</b>	<b>34.3</b>	<b>36.6</b>	<b>35.1</b>
सरकारी क्षेत्र	7.4	7.9	8.3	8.9	9.4	9.2	8.8
निजी क्षेत्र	23.8	25.2	26.4	28.1	24.8	25.2	24.9
कारपोरेट क्षेत्र	10.3	13.6	14.5	17.3	11.3	12.7	12.1
पारिवारिक क्षेत्र	13.4	11.7	11.9	10.8	13.5	12.4	12.8
<b>सकल नियत पूंजी निर्माण</b>	<b>28.7</b>	<b>30.3</b>	<b>31.3</b>	<b>32.9</b>	<b>32.3</b>	<b>31.6</b>	<b>30.4</b>
स्टॉक	2.5	2.8	3.4	4.0	1.9	2.7	3.3
मूल्यवान वस्तुएं	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.8	2.1
<b>बचत-निवेश अंतर</b>	<b>-0.4</b>	<b>-1.3</b>	<b>-1.1</b>	<b>-1.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>-2.8</b>	<b>-2.8</b>
सरकारी क्षेत्र	-5.1	-5.5	-4.7	-3.9	-8.5	-9.0	-7.1
निजी क्षेत्र	6.3	5.8	4.6	3.7	6.3	8.5	5.8

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

टिप्पणी : भूल-चूक और त्रुटियों के लिए किए गए समायोजन के कारण जोड़ में अंतर हो सकता है।



अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों को दिया जा सकता है जो वैयक्तिक निपटान योग्य आय के बजाए निजी अंतिम उपभोग व्यय की उच्चतर वृद्धि में परिणत हुई, और आंशिक श्रेय वास्तविक ब्याज दर में कमी को दिया जा सकता है।

1.9 2010-11 में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों, विशेषकर कॉरपोरेट क्षेत्र, की बचत दरों में कमी आई थी। 2010 के द्वितीयार्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन के संकेत दर्शित होने से, कॉरपोरेट निवेश में कमी का श्रेय वैश्विक कारकों के साथ-साथ घरेलू कारकों नामतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने के कारण उधार की बढ़ी हुई लागत, को दिया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में नियत निवेश 2007-08 में चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके बाद से इसमें हास होता रहा। 2009-10 में यह 31.6 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 30.4 प्रतिशत पर पहुंच गया।

1.10 सकल घरेलू उत्पाद के 2.8 प्रतिशत पर, 2010-11 के दौरान बचत-निवेश अंतर 2009-10 के स्तर पर ही बना रहा। इससे विदेशी बचतों (चालू लेखा घाटा) से निवेश अपेक्षाओं को वित्तपोषित करने की आवश्यकता प्रतिबिंबित हुई। सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कुछ अधिक यह अंतर, 2004-05 से 2007-08 में 0.4-1.3 प्रतिशत की तुलना में सापेक्षतया उच्च स्तरों पर (2008-09 से) बना हुआ है। सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों में बचत-निवेश अंतर 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कम हो गया। सरकारी क्षेत्र के लिए, यह अंतर सकल घरेलू उत्पाद के -9.0 प्रतिशत से कम होकर -7.1 प्रतिशत हो गया। यह अंतर 2008-09 से पहले के वर्षों में इससे भी काफी निम्नतर था। तथापि, 2008-09 की मंदी से निकलने के लिए दिए गए राजकोषीय प्रेरणों से सरकारी बचतें सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 2008-09 में 4 प्रतिशतांक कम हो गईं और फिर 2009-10 में अन्य 0.8 प्रतिशतांक कम हो गईं। वर्ष 2010-11 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण, राजस्व स्तरों में वृद्धि और राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र के बचत-निवेश अंतर को कम करने के लिए जिम्मेदार कारणों में से थे।

1.11 मध्यम से दीर्घ अवधि में, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की संवृद्धि, काफी हद तक, न केवल निवेश के समग्र स्तर पर, बल्कि, उसके क्षेत्रीय संघटन पर भी निर्भर करती है जिससे हो रहे परिवर्तन प्रतिबिम्बित होते हैं। तथापि, सकल और क्षेत्रीय स्तरों, दोनों पर निवेश की वार्षिक संवृद्धि दरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, जो लाभप्रदता, बिक्री आदि की प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। जैसाकि सारणी 1.5 से देखा जा सकता है, विगत समय में क्षेत्रों की वृद्धि दरों में बड़े पैमाने पर विभिन्नताएं हैं। 2010-11 में संचार और रेलवे को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों ने निवेश स्तरों में वास्तविक अर्थों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की। 2009-10 और 2010-11 में संचार में सीमान्तिक ऋणात्मक वृद्धि का होना इस क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में हुई अत्यधिक वृद्धि के पश्चात् विलक्षण नहीं है। रेलवे

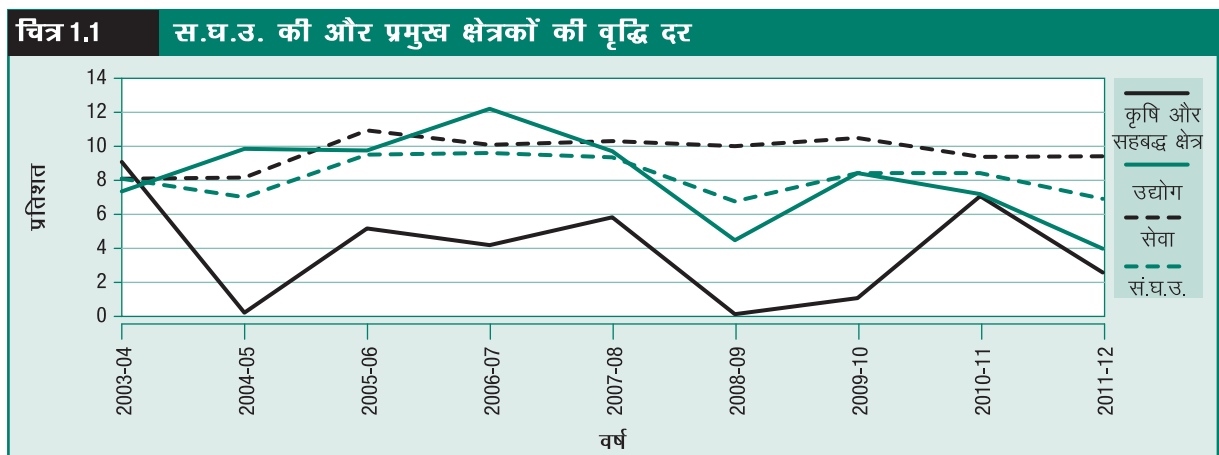
क्षेत्र में वास्तविक निवेश वृद्धि कई वर्षों तक धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाने के पश्चात् ऋणात्मक हो गई। यह अंशतः बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति करने के लिए प्रशुल्कों को बढ़ा सकने की असमर्थता को दर्शाता है।

1.12 पारंपरिक रूप से, आर्थिक समीक्षा मौजूदा वर्ष में हुए घटनाक्रमों का विवरण देती है; तथापि, दीर्घावधिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में, विशेषकर पश्च 1991 अवधि के संदर्भ में टिप्पणी करना और यह विचार करना उपयुक्त होगा कि हम वर्तमान काल में कहां खड़े हैं। 1950-51 और 1990-91 के बीच वृद्धि की दर 4.1 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 1991-92 और 2011-12 के बीच, अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि 1951-92 से 1991-92 तक के चार दशकों में, घटक लागत पर (2004-05 की कीमतों पर) सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वृद्धि दर केवल 10 वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक थी, 1992-93 और 2011-12 के बीच (2011-12 के लिए अंश सहित) (दोनों अवलोकनों को समाहित करके 20 वर्षों का समय अवधि) वृद्धि दर कुल 14 वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक रही है। 2003-04 से वृद्धि दरें महत्वपूर्ण रूप से त्वरित हो गईं। 2003-04 और 2011-12 के बीच, अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की। वास्तव में, इस अवधि के दौरान, वृद्धि दर कभी भी 6.7 प्रतिशत से कम नहीं हुई और इन नौ वर्षों में से 6 वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक पर रही है। अर्थव्यवस्था के सभी तीनों प्रमुख क्षेत्र नामतः कृषि, उद्योग और सेवा में क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 8.0 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत की रूझानों-से-उच्चतर वृद्धि दरें देखी गईं। स्पष्टतया, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। (संपूर्ण चर्चा के लिए अध्याय -10 देखें)। इस क्षेत्र की वृद्धि ने सबसे कम अंतर-अस्थायी भिन्नताएं दर्शायी है। कृषि क्षेत्र के हासित होते हुए हिस्से और सेवा क्षेत्र में युक्ति संगत निरंतर वृद्धि के साथ, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में विभिन्नताओं को विगत कुछ समय से उद्योग क्षेत्र में विभिन्नताओं से जोड़ा जा रहा है (चित्र 1.1)।

1.13 इस त्वरित संवृद्धि का आंशिक श्रेय बचत और निवेश दरों में वृद्धि को दिया जा सकता है, जो 2003-4 से 2010-11 की अवधि के दौरान क्रमशः औसतन 33.1 प्रतिशत और 34.3 प्रतिशत पर रहीं। 1990 के दशक में औसत बचत और निवेश दरें क्रमशः 23.0 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत थीं। इस वृद्धि को आगे और बनाए रखना तथा त्वरित करना समावेशी विकास कार्यसूची द्वारा यथाप्रतिबिंबित मानव कल्याण का संवर्धन करने की ओर लक्षित उच्चतर प्रति व्यक्ति आय और अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णायक होगा। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतर वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त तीव्र वृद्धि में परिणत हुई। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को 1950-51 में प्राप्त स्तर से दोगुने स्तर तक पहुंचाने में करीब 40 वर्ष लगे। तथापि सुधार-पश्च अवधि में अगले 20 वर्षों में यह 2.5 गुणा तक बढ़ गयी।

सारणी 1.5 : 2004-05 की कीमतों पर क्षेत्रक निवेश वृद्धि दरें	सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर					
	2005-206	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	13.8	6.3	14.9	20.2	3.2	8.5
कृषि	13.9	5.9	15.9	21.4	2.8	8.4
वानिकी और लॉगिंग	30.9	13.4	-20.3	-3.2	-11.9	3.8
मात्स्यिकी	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5
खनन और उत्खनन	40.0	15.7	13.1	-16.6	15.7	6.7
विनिर्माण	17.5	17.2	29.0	-31.3	42.3	7.1
पंजीकृत	39.3	11.0	37.1	-27.5	31.6	8.1
अपंजीकृत	-36.8	50.9	-3.7	-53.1	137.6	2.4
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	21.3	18.1	12.6	15.1	3.3	1.0
निर्माण कार्य	5.7	66.5	20.2	-23.1	-2.5	14.1
व्यापार, होटल और रेस्तरां	26.7	30.0	-14.7	28.7	-12.1	48.9
व्यापार	22.6	34.0	-20.1	35.8	-16.2	56.4
होटल और रेस्तरां	49.3	11.7	14.8	1.7	8.9	19.2
परिवहन, भंडारण और संचार	20.1	-6.7	25.3	53.8	-7.5	2.2
रेलवे	14.6	12.9	13.7	22.5	6.2	-9.5
अन्य साधनों द्वारा परिवहन	12.9	-14.2	28.7	30.8	-17.5	13.3
भंडारण	-285.9	18.0	5.7	71.9	-8.0	13.3
संचार	33.2	-6.7	29.3	110.6	-2.9	-2.4
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	6.2	2.4	8.9	41.4	-11.9	3.6
बैंकिंग और बीमा	70.4	61.8	-6.8	-28.0	0.0	54.5
स्थावर संपदा, आवासों का स्वामित्व, और व्यावसायिक सेवाएं	4.3	-0.4	10.1	45.9	-12.2	1.7
सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	19.6	12.5	18.2	-0.7	8.3	12.5
लोक प्रशासन और रक्षा	17.3	14.0	13.4	7.3	10.1	11.5
अन्य सेवाएं	22.7	10.7	24.5	-10.4	5.7	14.0
जोड़	17.0	15.3	17.7	-2.5	9.8	9.9

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन



## 8 आर्थिक समीक्षा 2011-12

1.14 कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के योगदानों में भी समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कृषि क्षेत्र में दीर्घावधिक वृद्धि दर (पिछले 60 वर्षों में) 2.7 प्रतिशत रही है। यह दर 1950-51 और 1980-81 के बीच 2.3 प्रतिशत थी और 1980-81 से 2011-12 के दौरान 3.1 प्रतिशत थी। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 1980-81 और 2011-12 के बीच पूर्ववर्ती अवधि में 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, इन दो उप-अवधियों के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत थी।

1.15 अर्थव्यवस्था की संरचना में भी समय के साथ-साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 1950-51 और 1980-81 के बीच, औद्योगिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। तब से यह मामला उलट गया है। इससे उद्योग क्षेत्र के हिस्से में सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 से 1980-81 की अवधि के दौरान 16.6 प्रतिशत से 25.9 प्रतिशत होकर लगभग 9 प्रतिशतांक से बढ़ गया। सेवा क्षेत्र का हिस्सा 1950-51 में 30.3 प्रतिशत से बढ़कर 1980-81 में 38 प्रतिशत हो गया। तत्पश्चात् यह तेज़ी से बढ़ने लगा और 1990 के दशक में यह संवृत्ति और सुस्पष्ट हो गयी। परिणामस्वरूप, 1980-81 से, उद्योग क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद के 26 से 28 प्रतिशत की श्रेणी में बना हुआ है जबकि कृषि के हिस्से में हुआ संपूर्ण हास सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि द्वारा संतुलित हो गया है। अतः, घातों के प्रति अर्थव्यवस्था का समुत्थान सेवा क्षेत्र के कारण हुआ है, जिसका हिस्सा सबसे बड़ा है और वृद्धि निष्पादन सर्वाधिक सतत् है। इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष हिस्सों में हुए परिवर्तनों को सारणी 1.6 में दर्शाया गया है।

**सारणी 1.6 : सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रीय संघटन**

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं
1950-51	53.1	16.6	30.3
1960-61	48.7	20.5	30.8
1970-71	42.3	24.0	33.8
1980-81	36.1	25.9	38.0
1990-91	29.6	27.7	42.7
2000-01	22.3	27.3	50.4
2010-11 <sup>व.अ.</sup>	14.5	27.8	57.7
2011-12 <sup>अ.अ.</sup>	13.9	27.0	59.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन आंकड़े से परिकल्पित

### सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक अनुमान

1.16 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 29 फरवरी, 2012 को वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही के अनुमान जारी किए। सारणी 1.7 में 2010-11 और 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों के लिए प्रमुख क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद की त्रैमासिक वृद्धि दरें दर्शाई गई हैं।

1.17 सकल घरेलू उत्पाद के अर्थों में, मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में घटक लागत पर वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2010-11 में क्रमशः 11.0 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत, और 7.7 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 2.7 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत बैठती है। यह देखा जा सकता है कि मौजूदा वर्ष की प्रत्येक अनुक्रमिक तिमाही में हुई वृद्धि पूर्ववर्ती तिमाही में हुई वृद्धि से कम रही है। मौजूदा वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में हुई वृद्धि एकसाथ मिलकर पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 6.9 प्रतिशत बैठती है। उद्योग

**सारणी 1.7 : पहली तीन तिमाहियों के लिए त्रैमासिक वृद्धि दर (प्रतिशत)**

क्षेत्र	2010-11			2011-12		
	तिमाही1	तिमाही2	तिमाही3	तिमाही1	तिमाही2	तिमाही3
1 कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी	3.1	4.9	11.0	3.9	3.2	2.7
उद्योग	8.3	5.7	7.6	5.1	3.2	2.6
2 खनन और उत्खनन	6.9	7.3	6.1	1.8	-2.9	-3.1
3 विनिर्माण	9.1	6.1	7.8	7.2	2.7	0.4
4 बिजली, गैस और जलापूर्ति	2.9	0.3	3.8	7.9	9.8	9.0
5 निर्माण कार्य	8.4	6.0	8.7	1.2	4.3	7.2
सेवाएं	10.0	9.1	7.7	10.0	9.3	8.9
6 व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	12.7	10.8	9.8	12.8	9.9	9.2
7 वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	10.0	10.4	11.2	9.1	10.5	9.0
8 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	4.4	4.5	-0.1	5.6	6.6	7.9
घटक लागत पर कुल स.घ.उ.	8.5	7.6	8.3	7.7	6.9	6.1

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन



और कृषि क्षेत्र में वृद्धि मंद होकर 3.6 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत हो गई, जबकि सेवा क्षेत्र ने अपनी वृद्धि में सुधार किया और यह 9.4 प्रतिशत हो गई। मौजूदा वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही।

## कृषि और खाद्य

1.18 संबद्ध कार्यकलापों सहित कृषि का हिस्सा 2004-05 की कीमतों पर 2010-11 में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद का 13.9 प्रतिशत था। संघटन के अर्थ में, 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में 14.5 प्रतिशत के कुल हिस्से में से, अकेले कृषि का हिस्सा 12.3 प्रतिशत था, जिसके बाद 1.4 प्रतिशत पर वानिकी और लॉगिंग, और 0.7 प्रतिशत पर मात्स्यिकी का हिस्सा था। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में ह्रासित होती हुई प्रवृद्धि के बावजूद, अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्व को रोजगार में इसके हिस्से के संदर्भ में और वृहत आर्थिक स्थायीत्व के लिए इसकी महत्ता के अर्थों में, बेहतर समझा जा सकता है। जबकि रोजगार में इस क्षेत्र के हिस्से की जानकारी पहले ही थी, वृहत आर्थिक स्थायीत्व के लिए इसकी महत्ता 2000 के दशक के मध्य से आय में बढ़ती रही होने से सुस्पष्ट हो गई।

1.19 अतः, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और समावेशी विकास के लिए एक 'अत्यावश्यक शर्त' बना हुआ है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में औसत वार्षिक वृद्धि 4 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर की तुलना में 3.3 प्रतिशत थी। इस क्षेत्र ने 2009-10 के दौरान देश के अधिकतर भागों में प्रचंड सूखा पड़ने के कारण और 2010-11 में कुछ राज्यों नामतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उ०प्र० और पश्चिम बंगाल में सूखा/कम वर्षा होने के कारण लक्षित से थोड़ी कम औसत वृद्धि दर्ज की। तथापि, सरकार द्वारा किए गए सम्योचित और सुधारात्मक उपायों ने कृषिय उत्पादन को बढ़ाने में मदद की और इस क्षेत्र में हुई वृद्धि 2010-11 में 7.0 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले छः वर्षों के दौरान हासिल सबसे उच्च वृद्धि दर है। 2011-12 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने का अनुमान है। तथापि, यह चिंता का विषय है कि कृषिय वृद्धि, अभी भी, कुछ सीमा तक प्रकृति की मौजों के कारण हुए उतार-चढ़ावों से प्रभावित होती है, यद्यपि 2002-03 से उत्पादन के अर्थ में कोई वास्तविक ह्रास नहीं हुआ है।

1.20 वर्षा महत्वपूर्ण रूप से फसल उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करती रहती है। 2011 में दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम

के दौरान, जब इस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत अधिक थी। स्थानिक वितरण के अर्थों में, इस मौसम के दौरान हुई वर्षा इस वर्ष कृषिय उत्पादन के वर्धन के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी।

1.21 2010-11 में, 244.78 मिलियन टन का सर्वाधिक रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 के दौरान 250.42 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है जिसका कारण देश के प्रमुख चावल-उत्पादकों में से कुछ राज्यों नामतः असम, बिहार, प० बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, में चावल के उत्पादन में हुई वृद्धि है।

1.22 1 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की भंडार स्थिति 55.2 मिलियन टन थी, जिसमें 31.8 मिलियन टन चावल और 23.4 मिलियन टन गेहूं शामिल है, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपेक्षाओं की पूर्ति और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त है। कृषिय उत्पादन के उच्चतर स्तर और प्रचुर खाद्य भंडार शीर्ष मुद्रास्फीति को कम करने के लिए शुभ होंगे।

## उद्योग और अवसंरचना

1.23 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) द्वारा यथामापित औद्योगिक वृद्धि अस्थिर प्रवृत्तियां दर्शाती है। वृद्धि 2007-08 में 15.5 प्रतिशत पर थी और फिर इसमें अवमंदन होने लगा। औद्योगिक वृद्धि में प्रारंभिक अवमंदन मुख्यतया वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण था। तथापि, इसमें समुत्थान हुआ और यह 2008-09 में 2.5 प्रतिशत से सुधरकर 2009-10 में 5.3 प्रतिशत और 2010-11 में 8.2 प्रतिशत हो गई। अमरीका और यूरोप में कमजोर आर्थिक समुत्थान और देश में सामान्यतः दमित प्रत्याशाओं ने मौजूदा वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित किया। अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान समग्र वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 8.3 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत पर रह गई।

1.24 खनन क्षेत्र में उत्पादन में संकुचन हुआ, विशेषकर कोयला और प्राकृतिक गैस खंडों में। उत्पादन में संकुचन के परिणामस्वरूप वृद्धि भी ऋणात्मक हो गई। मौजूदा वर्ष में विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में सुधार देखा गया। इस क्षेत्र ने समग्र औद्योगिक वृद्धि में 22.6 का प्रतिशत योगदान दिया, जो आईआईपी में इसके भार के दोगुने से अधिक था। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, अप्रैल-दिसंबर, 2010 में 9.0 प्रतिशत से गिरकर अप्रैल-दिसंबर, 2011 में 3.9 प्रतिशत रह गई, जिससे, आईआईपी में इसके विशाल हिस्से को देखते हुए, समस्त उद्योग क्षेत्र में अवमंदन हुआ।

## 10 आर्थिक समीक्षा 2011-12

1.25 मौजूदा वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में, आईआईपी में उपयोगाधारित वर्गीकरण के संबंध में, 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आधारीक वस्तुओं और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सापेक्षतया बेहतर रही थी। आईआईपी के अन्य खंडों में वृद्धि मंद थी और पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्तियों में ऋणात्मक वृद्धि अवलोकित की गई। आधारीक वस्तु खंड में 65.7 प्रतिशत की वृद्धि न केवल समग्र आईआईपी में अपने भार से अधिक थी, बल्कि आईआईपी में सबसे अधिक भी थी। 28.1 प्रतिशत पर उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का योगदान भी आईआईपी में अपने भार से अधिक था।

1.26 विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, आईआईपी 22 उपसमूहों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2004) के द्वि-अंकीय स्तर पर असकलित अलग से वृद्धि दरों की व्यवस्था करता है। उप-समूहों में वृद्धि भिन्न-भिन्न थी, जो यह निर्दिष्ट करती है कि यद्यपि विस्तृत वर्गीकरण के अर्थ में अवमंदन व्यापक लग सकता है, ऐसे खंड भी थे जिनमें बेहतर निष्पादन हुआ है। अप्रैल-दिसंबर, 2011 में आईआईपी में 29.23 प्रतिशत के भार के साथ ऐसे 7 विनिर्माण उप समूह थे, जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई; 26.6 प्रतिशत के 9 उप-समूहों में वृद्धि धनात्मक थी किन्तु 10 प्रतिशत से कम थी; और 19.7 प्रतिशत के भार वाले 6 उप-समूह थे जिनमें वृद्धि ऋणात्मक थी। यद्यपि मौजूदा वर्ष में, ऐसे उप समूहों की संख्या बढ़ी है, जिन्होंने भार (सापेक्ष महत्व) के अर्थ में द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की, अन्य क्षेत्रकों में तीव्रतर मंदी सकल वृद्धि के द्वासे में परिणत हुई।

1.27 निगम-क्षेत्र बिक्रियां औद्योगिक निष्पादन का एक अन्य संकेतक है। सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्रियों में विशाल वृद्धि (अभिहित अर्थों में) निर्दिष्ट करते हैं। मौजूदा वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में, बिक्री वृद्धि 20 और 25 प्रतिशत के बीच रही। यद्यपि बिक्री वृद्धि 2009-10 की चौथी तिमाही में 34.9 प्रतिशत के शीर्ष से उतरकर मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में 22.6 प्रतिशत पर कम हो गई है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 19.0 प्रतिशत से बेहतर है। तथापि, व्यय वृद्धि ने राजस्व वृद्धि को पछाड़ दिया जिससे निवल लाभों में कम वृद्धि हुई, जो अंतिम दो तिमाहियों में कम हो गए। उच्चतर व्यय वृद्धि आरंभतः उच्च कच्चे माल व्ययों से शुरू हुई, किन्तु 2011-12 की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में ब्याज व्यय और अधिक तीव्रता से बढ़ गए।

1.28 आठ मूल उद्योगों में उत्पादन जनवरी, 2011 में 0.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जनवरी, 2012 में 6.4 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-जनवरी 2011-12 में संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी

अवधि के दौरान 5.7 प्रतिशत की तुलना में 4.1 प्रतिशत रही। जबकि, चार क्षेत्रों नामतः कोयला, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत ने जनवरी, 2012 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शायी, अन्य चार क्षेत्रों, अर्थात् कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिष्करणशाला उत्पादों और इस्पात ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। यद्यपि मौजूदा वर्ष के दौरान कोयले में संचयी संवृद्धि अभी तक ऋणात्मक बनी हुई है, पिछले तीन महीनों में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। सीमेंट क्षेत्र में उत्पादन ने भी पिछले तीन महीनों (नवम्बर-जनवरी 2011-12) में द्विअंकीय वृद्धि दर्शाई है।

1.29 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली सभी केन्द्रीय-क्षेत्र परियोजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण कर रहा है। अक्टूबर 2011 के माह संबंधी फ्लैश रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में 583 परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखती है। इनमें से केवल 7, अपने निर्धारित समय से पूर्व चल रही हैं, 166 निर्धारित समय पर चल रही हैं और 235 विलंबित हैं (175 परियोजनाओं को शुरू करने का समय विनिर्दिष्ट किए बिना मंजूरी दे दी गई थी)। ये विलंब 15.3 प्रतिशत के लागत आधिक्य का संकेत भी करते हैं। सबसे अधिक विलंबित परियोजनाओं का संबंध सड़क परिवहन और राजमार्ग (90) से है जिसके बाद विद्युत (45), पेट्रोलियम (29), रेलवे (26), और कोयला (17) का स्थान है। जैसा कि राष्ट्रीय लेखों और साथ ही आईआईपी आंकड़ों से स्पष्ट है, इस वर्ष बिजली क्षेत्र अच्छा निष्पादन कर रहा है।

1.30 2011-12 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं द्वारा बिजली के सृजन का 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 855 बिलियन यूनिट पर पहुंचने का लक्ष्य है। अप्रैल-जनवरी 2010-2011 के दौरान 5.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जनवरी 2011-12 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि 8.6 प्रतिशत थी। 2011 के पहले नौ महीनों में, उत्पादन लक्ष्य का 76 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। समग्र संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) जो तापविद्युत स्टेशनों की क्षमता का एक पैमाना है, अप्रैल-दिसंबर, 2010 के दौरान हासिल किए गए 72.9 के पीएलएफ से अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान 72.1 प्रतिशत पर सीमान्तिक रूप से कम था। तथापि, मौजूदा वर्ष में पीएलएफ, पहली तीन तिमाहियों में 68.2 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 38.19 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) होना अनुमानित है जो 2010-11 के दौरान उत्पादित 37.70 एमएमटी की तुलना में लगभग 1.33 प्रतिशत उच्चतर है। अप्रैल-दिसम्बर 2011-12 के दौरान घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 28.70 एमएमटी था जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कोकिंग-भिन्न कोयला भारत में कोयला उत्पादन के 90 प्रतिशत से अधिक था।

वर्तमान वर्ष तथा विगत वर्ष के दौरान उत्पादन में निम्नतर वृद्धि मुख्यतः पर्यावरणीय प्रतिबंधों, व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईजीआई) के अनुप्रयोग, कुछ परियोजनाओं के लिए वानिकी समाशोधन की अनुपलब्धता, झारखंड तथा उड़ीसा के राज्यों में निकृष्ट कानून और व्यवस्था स्थिति तथा कोयला खनन क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टिपात के कारण हुई है। निम्नतर घरेलू उत्पादन ने आयातों पर निर्भरता बढ़ा दी है तथा परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 में 68.9 एमटी कोयले का आयात किया गया था।

1.31 भारतीय रेलवे की माल ढुलाई अप्रैल-नवम्बर 2010 में 593.4 एमटी की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 2011 के दौरान 618.0 एमटी थी जो 4.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है। यह 644.6 एमटी के आनुपातिक लक्ष्य से 26.6 एमटी कम है। निम्न वृद्धि का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों में सापेक्षतया धीमी वृद्धि का होना है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात तथा राज्य सरकारों से स्वीकृति प्राप्त करने में प्रक्रियागत समस्याओं के कारण लौह अयस्क में ऋणात्मक वृद्धि द्वारा यह वृद्धि और भी धीमी हो गई। भारत में हवाई यातायात ने पिछले सात वर्षों में औसत 18.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ वृद्धि की महत्वपूर्ण उच्चतर दरें दर्ज करना जारी रखा है। भारतीय हवाई पत्तनों पर प्रहस्तित घरेलू यात्री यातायात जनवरी-नवम्बर 2011 में विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि के 90.5 मिलियन के स्तर से 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 108.1 मिलियन पर पहुंच गया। भारतीय हवाई पत्तनों में प्रहस्तित, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात तथा कार्गो में जनवरी-नवम्बर 2011 के दौरान 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इसे 33.6 मिलियन यात्रियों तथा 1.4 एमएमटी कार्गो पर रखा गया है। जनवरी-नवम्बर 2011 की अवधि के दौरान घरेलू कार्गो थ्रूपुट 0.75 एमएमटी था जो विगत वर्ष के स्तर के समतुल्य ही है।

1.32 दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि जारी रही तथा 31 मार्च 2007 को 206.8 मिलियन टेलीफोनोनों की कुल संख्या की तुलना में 31 दिसम्बर 2011 को टेलीफोनोनों की संख्या 926.95 मिलियन थी। दूर-सघनता देश में दूरभाष अंतर्वेधन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह मार्च 2007 में 18.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 2011 में 76.8 प्रतिशत हो गया है। दूर सघनता विभिन्न मंडलों में भिन्न है तथा शहरी ग्रामीण दूरसघनता में काफी अधिक अंतर है। दिसम्बर 2011 के अंत में जबकि शहरी क्षेत्रों की दूर सघनता 167.4 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, ग्रामीण दूर सघनता केवल 37.5 प्रतिशत थी। पत्तन क्षेत्र में, भारत में प्रमुख तथा लघु पत्तनों ने अप्रैल-सितम्बर 2011 के दौरान 446.1 एमटी का कुल कार्गो थ्रूपुट प्रहस्तित किया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। 12 प्रमुख पत्तनों में प्रहस्तित कार्गो की वृद्धि दर

अप्रैल-सितम्बर 2010 में 1.2 प्रतिशत से सुधर कर अप्रैल-सितम्बर 2011 में 3.1 प्रतिशत हो गई। तथापि, लघु पत्तनों में प्रहस्तित कार्गो की वृद्धि अप्रैल-सितम्बर 2010 में 22.2 प्रतिशत की तुलना में हासित होकर अप्रैल-सितम्बर 2011 में 7.2 प्रतिशत रह गई।

## सेवा क्षेत्र

1.33 अग्रिम अनुमानों के अनुसार घटक लागत (वर्तमान मूल्यों पर) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 1950-51 में 33.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 55.1 प्रतिशत तथा 2011-12 में 56.3 प्रतिशत हो गया। एक समूह के रूप में व्यापार, होटल तथा रेस्तरां का 16.9 प्रतिशत के अंश के साथ विभिन्न सेवा उपक्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान था जिसके पश्चात 16.4 प्रतिशत अंश के साथ वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसाय सेवाओं का स्थान है। सतत कीमतों पर सेवा क्षेत्रक संवृद्धि दर वर्ष 2003-04 को छोड़कर वर्ष 1996-97 से सदैव समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से उच्च रही है। वर्ष 2004-05 से 2010-11 की अवधि के लिए 10.2 प्रतिशत पर सेवा क्षेत्र की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) इसी अवधि के दौरान 8.6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से उच्चतर रही है। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में, सेवा क्षेत्र ने क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2011-12 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवाओं की वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत रखी गई है।

1.34 हालांकि कृषि प्राथमिक रोजगार प्रदायक क्षेत्र बना हुआ है, सेवा क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में रोजगार का प्रधान स्रोत है। “भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति, 2009-10” पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार नियोजित प्रति 1000 व्यक्तियों में से कृषि क्षेत्र में 679 तथा 75 लोग क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नियोजित हैं (प्रधान प्रास्थिति में तथा अनुषंगी प्रास्थिति में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में मापित)। दूसरी ओर सेवा क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियोजित प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में से क्रमशः 147 तथा 582 नियोजनों के लिए उत्तरदायी है।

## कीमतें

1.35 शीर्ष रेखा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष 2011 के दौरान लगभग 9 प्रतिशत पर निरंतर उच्च तथा सापेक्षतया स्थिर रही। यद्यपि मुद्रास्फीति सम्पूर्ण वर्ष उच्च रही थी, हाल ही में इसने कमी के संकेत दर्शाए हैं। इस प्रवृत्ति का एक ऐसा संकेतक थोक मूल्य सूचकांक के सभी प्रमुख समूहों में मौसमी रूप से समायोजित तीन माह के चल औसत आंकड़े हैं (चित्र 1.2)। वित्तीय वर्ष

2011-12 की शुरुआत 9.7 प्रतिशत की शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति के साथ हुई जो जनवरी 2012 में कम होकर 6.6 प्रतिशत पर पहुंचने से पूर्व सितम्बर 2011 में थोड़े से समय के लिए द्विअंकीय हो गई थी। प्रमुख सूचकांकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति घटकर दिसम्बर 2011 में 7 प्रतिशत से कम रह गई।

1.36 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति के प्रमुख अंशदायी कारकों में ये शामिल हैं:- (क) उपभोक्ताओं के बदलते आहारिय पैटर्न के कारण सब्जियों, अंडों, मांस तथा मछली द्वारा चालित उच्चतर प्राथमिक मर्दें; (ख) बढ़ती वैश्विक वस्तु कीमतें विशेषतया धातु तथा रसायन कीमतें जो अंततः उच्चतर घरेलू विनिर्माण कीमतों में परिणामी हुई; तथा (ग) विगत दो वर्षों में कच्चे पेट्रोलियम की निरंतर उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो 2010 में 80 डालर प्रति बीबीएल की तुलना में 2011(जनवरी-दिसम्बर) में औसतन 111 डालर प्रति बैरल (बीबी एल) रही।

1.37 विगत दशक के पूर्ववर्ती भाग में सापेक्षतया स्थिर मुद्रास्फीतिकारी अवधि की तुलना में औसत शीर्ष रेखा थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष 2008-09 में बढ़नी शुरू हुई तथा इसका बढ़ना जारी रहा। दबाव मुख्यतः प्राथमिक तथा ईंधन उत्पादों की ओर से था जिनकी औसत मुद्रास्फीति वर्ष 2008-09 से काफी अवधि तक निरंतर द्विअंकीय बनी रही। इसकी तुलना में, विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति सापेक्षतया स्थिर रहती हुई वर्ष 2009-10 में तीव्रता से गिरी जिसका कारण वैश्विक आर्थिक संकट तथा भारत में इसके प्रभाव का होना था, इसके पश्चात यह बढ़नी शुरू हो गई तथा 2011-12 की आरम्भिक अवधि में लगभग 5 प्रतिशत से अपने दीर्घावधिक औसत को पार कर गई। व्यष्टि उत्पाद समूहों में, खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों वस्त्रों, रसायनों तथा आधारिक धातुओं में मुद्रास्फीति मुख्यतः उच्च वैश्विक वस्तु कीमतों के कारण उच्च बनी रही।

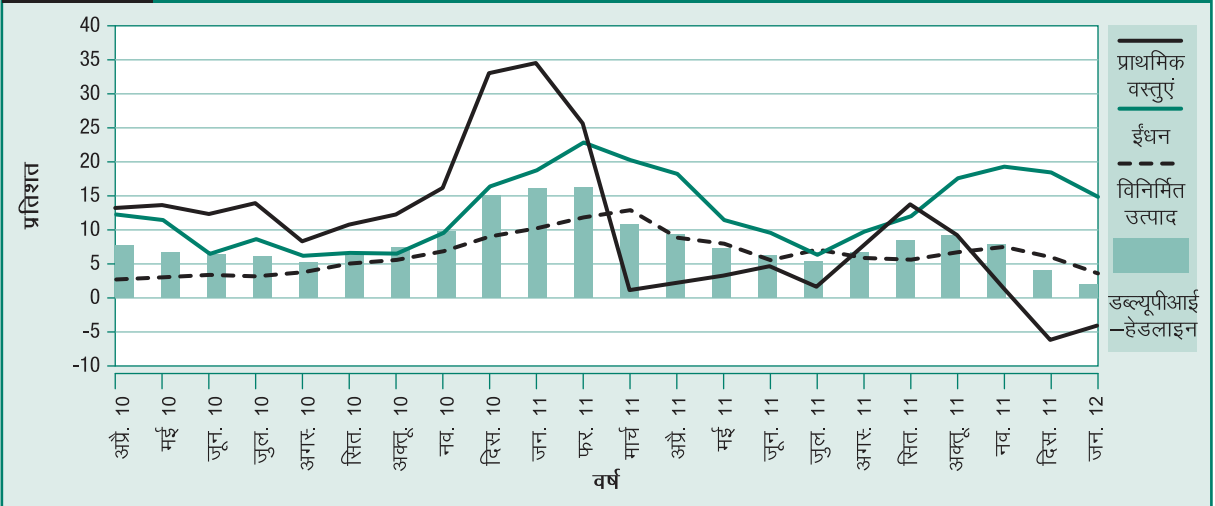
1.38 थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति (भारंश 24.31 प्रतिशत) फरवरी 2010 में 20.2 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से कम

हो कर जनवरी, 2012 में 1.6 प्रतिशत रह गई है जिसका मुख्य कारण फलों तथा सब्जियों की कीमत में मौसमी गिरावट का होना तथा अच्छी फसल का होना है जो अनाज में निम्नतर मुद्रास्फीति में परिणामी हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य चालक थे दूध, अंडे/मांस/मछली, चने तथा खाद्य तेल। विगत वर्ष की तुलना में विशेषतः खाद्य तेल से उच्चतर अंशदान जब अनाज, सब्जियां तथा चीनी खाद्य मुद्रास्फीति के मुख्य योगदाता थे, वर्ष 2011-12 में विनिर्मित खाद्य उत्पादों, परिलक्षित हुआ जो सोयाबीन के तेल, पॉम तेल इत्यादि की उच्चतर वैश्विक कीमतों के कारण था।

1.39 वर्तमान वित्तीय वर्ष (2011-12) में, थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में अंतर खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण रूप से संकीर्ण हो गया है। औद्योगिक कामगारों (आई डब्ल्यू) के लिए सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2010 से अगस्त 2011 तक एकल अंक में रहने के पश्चात, जनवरी 2012 में 5.3 प्रतिशत तक हासिल होने से पूर्व सितम्बर 2011 में एक लघु समय के लिए 10.1 प्रतिशत पर द्विअंकीय हो गई। सीपीआई-आईडब्ल्यू की खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी 2012 में 0.5 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मर्दों की (भारंश 14.34 प्रतिशत) मुद्रास्फीति जनवरी 2012 में ऋणात्मक हो गई थी।

1.40 सीपीआई (शहरी), सीपीआई (ग्रामीण) तथा सीपीआई (संयुक्त) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा हाल ही में यथानिर्मुक्त वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति जनवरी 2012 में क्रमशः 8.25 प्रतिशत, 7.38 प्रतिशत तथा 7.65 प्रतिशत थी। हालांकि सटीक तुलना करना संभव नहीं है जनवरी 2012 के लिए सीएसओ द्वारा यथा निर्मुक्त सीपीआई (ग्रामीण) मुद्रास्फीति दर (7.38 प्रतिशत) श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ द्वारा यथा निर्मुक्त सीपीआई (ग्रामीण क्षेत्र) (5.27 प्रतिशत) से विस्तार तथा भारंश (खपत) पैटर्नों में अंतर के कारण उच्चतर सूचित की गई है।

**चित्र 1.2 थोक मूल्य सूचकांक के उप-समूहों में संवेग (3-एम-3 अमौसमीकृत)**





## मौद्रिक प्रबंधन

1.41 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना वर्ष 2011-12 के दौरान मौद्रिक नीति के प्रबल उद्देश्य थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 तथा जनवरी 2012 के बीच रिपो दर को 13 बार बढ़ाकर इस में 375 आधार बिन्दुओं की संचयी वृद्धि की। आपूर्ति पक्ष के कारकों द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने तथा प्रगत देशों में अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य के कारण, जिसके कारण अधोमुखी प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए इन देशों द्वारा आवृत्त नकदी अंतर्वेशनों की आवश्यकता हुई, मौद्रिक नीति अंशांकन का कार्य विशेषतया चुनौतीपूर्ण था, स्थायी दर वृद्धियों ने एक सीमा तक संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। तथापि, दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 की अवधि में इस चक्र में उल्लेखनीय प्रतिवर्तन हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही की समीक्षा में रिपो तथा प्रतिवर्ती रिपो दरों को क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। तथापि, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) नकदी की स्थिति को सहज बनाने तथा संवृद्धि के पुनरुज्जीवन में सहायता करने के उद्देश्य से 6.0 से घटा कर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

1.42 मौद्रिक नीति की प्रचालन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रभावी किए गए हैं जिसमें भारांशित औसत एकदिवसीय मांग मुद्रा दर को प्रचालनात्मक लक्ष्य बनाया गया है तथा रिपो दर को एकमात्र स्वतंत्र परिवर्ती नीति दर विनिर्दिष्ट किया गया है। एक नवीन सीमांतिक स्थायी सुविधा (एमएसएफ) संस्थापित की गई है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को अपने विवेक पर एक ही दिन में अपनी संबंधित निवल मांग तथा समय देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक का उधार रिपो दर से 100 आधार बिंदु ऊपर पर लेने की अनुमति दी गई है। संशोधित गलियारे को 200 आधार बिंदु की नियत चौड़ाई के साथ परिभाषित किया गया है तथा रिपो दर को गलियारे के मध्य में और प्रतिवर्ती रिपो दर को उससे 100 आधार बिंदु नीचे रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 2012 को एक-समय तकनीकी समायोजन के रूप में आगे बैंक दर को 9.5 प्रतिशत की एमएसएफ दर के साथ सरेखित किया है।

1.43 वर्ष 2011-12 के दौरान, प्रारक्षित मुद्रा में संवृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रही है (10 फरवरी 2012 की स्थिति के अनुसार) जबकि स्थूल मुद्रा की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत रही है (27 जनवरी 2012 के अनुसार)। वर्षानुवर्ष खाद्य भिन्न ऋण संवृद्धि दिसम्बर 2011 के अंत में 15.7 प्रतिशत थी। नकदी की स्थिति 2011-12 के दौरान सामान्यतः घाटे में रही है जिसमें राजकोषीय वर्ष की शुरुआत एक संक्षिप्त अवधि के लिए समावेशन स्थिति में नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के साथ आरम्भ हो कर अप्रैल 2011 से घाटे की स्थिति में प्रतिवर्तन द्वारा अनुसरित हुई। तिमाही अग्रिम कर बहिर्प्रवाहों के कारण जून 2010 के दौरान नकदी पर कुछ दबाव उत्पन्न हुआ। यह दबाव अन्य बातों के अलावा लगभग 37,000 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिभूति के मोचन के साथ जुलाई 2011

में सहज हो गया। वर्ष 2011-12 के प्रथमाद्ध के दौरान, एमएसएफ के तहत नकदी का अंतर्वेशन दो अवसरों तक सीमित था। नवम्बर तथा दिसम्बर 2011 के दौरान नकदी घाटे की स्थिति में बनी रही जो जनवरी 2012 तक इसी स्थिति में बनी रही। वर्ष 2011-12 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक साधनों के जरिए नकदी के सरोकारों पर ध्यान दिया। ये साधन थे: खुला बाजार प्रचालन (ओएमओ खरीद तथा उपाय जिनमें दिसम्बर 2011 में एलएएफ के तहत अतिरिक्त रिपो प्रचालन शामिल है; तथा बैंकों को विद्यमान सुविधा जो उन्हें उनके संबंधित एनडीटीएल के 1 प्रतिशत तक की निधियों का अभिगम करने की अनुमति देती है, के अतिरिक्त एमएसएफ के तहत एक दिवसीय आधार पर निधियों को प्राप्त करने की अनुमति देना (उनके आधिक्य सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) धारिताओं के प्रति)। नकदी की स्थिति को सहज बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2011 से मध्य-जनवरी 2012 की अवधि के दौरान 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की सकल राशि के ओएमओ संचालित किए।

## वित्तीय मध्यस्थता और बाजार

1.44 कमजोर वैश्विक आर्थिक संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अनिश्चितताएं बने रहने से उनका प्रभाव भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ चुका है। विशेषकर यूरो क्षेत्र में व्याप्त साँवरेन ऋण के जोखिम संबंधी सरोकारों ने वर्ष के अधिकांश समय में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया और यूनान के साँवरेन ऋण की समस्या का असर 'सामान्य से अधिक' अस्थिरता के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर छा गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में निधिपोषण संबंधी अडचनों, बैंकों एवं कम्पनियों के लिए विदेशी निधिपोषण की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती हैं क्योंकि भारतीय वित्तीय तंत्र पर बैंक का प्रभुत्व है और इसलिए समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए दबावों को सह सकने की बैंकों की क्षमता बहुत महत्व रखती है। तथापि, अभी हाल में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात में हुई गिरावट और अनर्जक आस्तियों के स्तरों में उछाल आने के बावजूद भारतीय बैंकों की मजबूती बरकरार है। पूंजी पर्याप्तता स्तर विनियामक अपेक्षाओं से अधिक है।

1.45 ब्याज दरों के क्रमिक विनियंत्रण को देखते हुए, 25 अक्टूबर 2011 से बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन समाप्त कर दिया जहां बैंकों को 1 लाख रुपये तक की जमा राशि वाले बचत खातों पर एक-समान ब्याज दर रखनी होगी, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक की बचत बैंक जमा राशियों पर विभेदक ब्याज दरें तय की जा सकती हैं। इस विनियंत्रण से मौद्रिक नीति के सम्प्रेषण में सुधार आने की उम्मीद है। इससे यह भी आशा है कि बचत बैंक दर को बाजार की बदलती स्थितियों के अनुरूप निर्धारित करके बचत खातों के आकर्षण में बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

1.46 देश में आने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के प्रवाहों के सुस्त पड़ने के परिणामस्वरूप भारतीय बाजारों में गिरावट आई और विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये का तीव्र मूल्य हास हुआ, हालांकि यह मूल्य हास अधिकांशतः यूरोप में आई मन्दी और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के चलते विदेशी निवेशकों द्वारा “सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन” करने के कारण हुआ था। अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी आने से भी बाजार संवेग प्रभावित हुए हैं। विकास में कमी अनेक कारणों से आई है जिनमें वैश्विक माहौल में व्याप्त अनिश्चितता और मौद्रिक नीति को सख्त बनाने का अंतराल-प्रभाव शामिल है। अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को जनवरी 2012 में भारतीय इक्विटी बाजार में सीधे निवेश करने की अनुमति दी गई थी। ऐसा निवेशकों का वर्ग व्यापक करने, अधिक विदेशी निधियां आकर्षित करने, बाजार की अस्थिरता कम करने और भारतीय पूंजी बाजार को मजबूती देने के लिए किया गया था। इससे पहले, केवल एफआईआई/उप खातों तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय इक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी गई थी।

1.47 नवम्बर 2011 में, वैश्विक वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों और बृहत आर्थिक स्थितियों को देखते हुए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति संशोधित की गई थी। ऑल-इन-कॉस्ट की उच्चतम सीमा बढ़ा दी गई थी और भारत में रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई ईसीबी की प्राप्तियों को तत्काल लाए जाने की अपेक्षा रखी गई। ऑल-इन-कॉस्ट की उच्चतम सीमा में किया गया परिवर्तन तत्काल प्रवृत्त किया गया और 31 मार्च 2012 तक प्रयोज्य है तथा यह बाद में समीक्षा किए जाने के अध्वधीन है। अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक सम्पोषणीय विकास की कुंजी अवसंरचना विकास है। लेकिन बैंक द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता के चलते अवसंरचना का वित्तपोषण एक बाधा बना हुआ है। इसलिए कारपोरेट बांडबाजार का विकास अवसंरचना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्विप से इस प्रक्रिया में मदद मिलने की संभावना है, फिर भी कारपोरेट बांड बाजार को अवसंरचना के वित्तपोषण का प्रधान घटक बनाने के लिए नवीन परिवर्तनों की जरूरत है।

## अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1.48 भारत के व्यापार में उत्साह इस तथ्य से दृश्य है कि निर्यातों तथा आयातों की वृद्धि, जो 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप 2009-10 में क्रमशः (-)3.5 प्रतिशत तथा (-)5 प्रतिशत के बीच थी, वर्ष 2010-11 में पुनः उछल कर 40.5 प्रतिशत तथा 28.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत निर्यातों में न केवल पूर्व संकट स्तरों पर पहुंच गया बल्कि इसने निर्यात वृद्धि दर में पूर्व संकट प्रवृत्तियों को भी पीछे छोड़ दिया जो अनेक अन्य विकासशील तथा यहां तक कि कई विकसित देशों में प्रवृत्त रूझान

से भिन्न था। वैश्विक निर्यातों तथा आयातों में भी वृद्धि हुई जो वर्ष 2000 में क्रमशः 0.7 प्रतिशत तथा 0.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010 में 1.5 प्रतिशत तथा 2.2 प्रतिशत हो गए (विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अनुसार 1.4 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत)।

1.49 2011-12 के प्रथमाद्ध के दौरान, भारत के निर्यात में 40.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि देखी गई। तथापि, अक्टूबर 2011 से यूरो क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के गौण क्षेत्रों से आरंभ होकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल गए संकट के परिणामस्वरूप इसमें गिरावट आई है। नवम्बर, 2011 में, निर्यात वृद्धि दर (-)0.5 प्रतिशत पर थी और दिसम्बर, 2011 और जनवरी 2012 में यह सकारात्मक थी परन्तु 6.7 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत पर क्रमशः अल्प थी। संचयी निर्यात 242.8 बिलियन अमरीकी डालर थे, जिसमें 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के दौरान बेहतर निष्पादन करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं पेट्रोलियम और तेल उत्पाद, रत्न व जेवरात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सूती फेब्रिक, तैयार शुदा वस्तुएं, इलेक्ट्रानिक्स, रेडीमेड गारमेंट और औषधियां।

1.50 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में आयात 391.5 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें 29.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इस अवधि के दौरान पीओएल आयात 118 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें 38.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 273.5 बिलियन के पीओएल भिन्न आयात में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोने और चांदी का आयात 50 बिलियन अमरीकी डालर था जो 46.2 प्रतिशत बढ़ा। पीओएल-भिन्न और गैर सर्राफा आयात, जो मूलरूप से औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात और निर्यातों के लिए आवश्यक आयात को परिलक्षित करता है, 223 बिलियन अमरीकी डालर आंका गया और इसमें 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार घाटा (सीमाशुल्क आधार पर) 2009-10 में 109.6 बिलियन अमरीकी डालर से 8.2 प्रतिशत बढ़कर 2010-11 में 118.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि, 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) में 148.7 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा 2010-11 (अप्रैल-जनवरी) में 105.9 बिलियन अमरीकी डालर की अपेक्षा 40.4 प्रतिशत अधिक था।

1.51 भारत ने निर्यात और आयात बाजारों के सफलतापूर्वक विविधीकरण में उन्नति की है। कुल व्यापार में एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की हिस्सेदारी 2000-1 में 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 के प्रथमाद्ध में 57.3 प्रतिशत हो गई जबकि यूरोप और अमरीका की हिस्सेदारी 26.8 प्रतिशत से कम होकर 19 प्रतिशत रह गई। इससे भारत को यूरोप और अमरीका से उत्पन्न हुए वैश्विक संकट का सामना करने में मदद मिली है। 2008-09 के बाद से भारत के सबसे बड़े कारोबारी भागीदारी के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका का स्थान यूई ने ले लिया है जिसके बाद चीन का स्थान है।



## भुगतान संतुलन

1.52 2011-12 के दौरान भुगतान संतुलन घटनाक्रमों का मुख्य बिंदु वर्ष की पहली छमाही में 150.9 बिलियन अमरीकी डालर का मर्केन्डाईज निर्यात था, जो 2010-11 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का द्योतक है। अप्रैल-सितंबर, 2011 के दौरान 236.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयातों में अप्रैल-सितंबर, 2010 की तुलना में 34.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। व्यापार घाटा 2010-11 की पहली छमाही में 68.9 मिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 8.9 प्रतिशत) की तुलना में 2011-12 की प्रथम छमाही के दौरान 85.8 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 9.4 प्रतिशत) से अधिक था। ऐसा मुख्यतया 2011-12 की पहली छमाही के दौरान आयातित वस्तुओं नामतः तेल और सोना तथा चांदी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण था।

1.53 2011-12 की पहली छमाही के दौरान 52.9 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत) के निवल अदृश्य अधिशेष अप्रैल-सितंबर, 2010 के दौरान 39.3 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद) का 5.1 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर था। अदृश्यों की सभी विस्तृत श्रेणियों, अर्थात् सेवाएं, अंतरण और आय ने 2011-12 की पहली छमाही के दौरान वृद्धि दर्शायी। 2011-12 की पहली छमाही में मौजूदा लेखा घाटा 2010-11 की तदनुसूची अवधि के दौरान 29.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 32.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिसका मुख्य कारण उच्चतर व्यापार घाटे को माना गया।

1.54 2011-12 की पहली छमाही के दौरान 41.1 बिलियन अमरीकी डालर पर निवल पूंजी अंतर्वाह 2010-11 की पहली छमाही में 38.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अधिक बने रहे। निवल पूंजी अंतर्वाहों के अंतर्गत, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में 2010-11 की पहली छमाही में 7.0 बिलियन अमरीकी डालर में 2011-12 की तदनुसूची अवधि में 12.3 बिलियन अमरीकी डालर पर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी। इसी प्रकार 2011-12 की पहली छमाही के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधार 2010-11 की पहली छमाही में 5.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 10.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश और अमरीकी निक्षेपागार प्राप्तियां (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां (जीडीआर), समाहित पोर्टफोलियो निवेशों में अंतर्वाहों में भारी गिरावट देखी गई जो 2010-11 की पहली छमाही में 23.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2011-12 की पहली छमाही में 1.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निवल पूंजी अंतर्वाहों ने संतुलित कमी दर्शायी जो 2010-11 की पहली छमाही में 5.0 प्रतिशत से 2011-12 की पहली छमाही में 4.5 प्रतिशत हो गए। 2011-12 की पहली छमाही में आरक्षणों के प्रति निवल उपचय पिछले वर्ष की पहली छमाही में 7.0 बिलियन

अमरीकी डालर की तुलना में 5.7 बिलियन अमरीकी डालर पर निम्नतर था, जिसका मुख्य कारण चालू खाता घाटे का व्यापक होना था।

## विदेशी मुद्रा भंडार

1.55 राजकोषीय वर्ष 2010-11 में, विदेशी मुद्रा भंडार मार्चान्त 2010 में 279.1 बिलियन अमरीकी डालर से 25.7 बिलियन अमरीकी डालर बढ़कर मार्चान्त 2011 में 304.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। आरक्षणों में कुल वृद्धि में से, 12.6 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्यहास से उत्पन्न मूल्यांकन लाभों के कारण थी और शेष 13.1 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि भुगतान संतुलन के आधार पर थी। 2011-12 में, आरक्षण मार्चान्त 2011 में 304.8 बिलियन अमरीकी डालर से 6.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर सितंबर अंत 2011 तक 311.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। इस कुल वृद्धि में से 5.7 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि भुगतान संतुलन के आधार पर थी और शेष 1.0 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि मूल्यांकन प्रभाव के कारण थी।

1.56 मौजूदा राजकोषीय वर्ष में, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े एवं तब घटे। ये भंडार अगस्त-अंत 2011 में 322.2 बिलियन अमरीकी डालर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। तथापि, ये सितंबर अंत 2011 में कम होकर 311.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। दिसंबर अंत 2011 में, भंडार 296.7 बिलियन अमरीकी डालर पर थे और जनवरी अंत 2012 में 292.8 बिलियन अमरीकी डालर पर, जो मार्चान्त 2011 में 304.8 बिलियन अमरीकी डालर से 12.0 बिलियन अमरीकी डालर की कमी निर्दिष्ट करते हैं।

## विनिमय दर

1.57 मौजूदा राजकोषीय वर्ष में, माह-दर-माह आधार पर रूपए में 12.4 प्रतिशत का हास हुआ। यह मार्च 2011 में 44.97 प्रति अमरीकी डालर से जनवरी 2012 में 51.34 प्रति अमरीकी डालर हो गया। बिंदु-दर-बिंदु आधार पर 31 मार्च, 2011 को 44.65 प्रति अमरीकी डालर से 16.2 प्रतिशत हासित होकर 30 दिसम्बर, 2011 को 53.26 प्रति अमरीकी डालर हो गया। भारतीय रुपया 27 जुलाई, 2011 को 43.94 के अपने शीर्ष स्तर पर और 15 दिसम्बर 2011 को 54.23 प्रति अमरीकी डालर के निम्न स्तर पर पहुंच गया, जो 19.0 प्रतिशत का अवमूल्यन निर्दिष्ट करता है। इसी प्रकार, मार्च 2011 और दिसंबर, 2011 के बीच रूपए की मासिक औसत विनिमय दर में पाऊंड स्टर्लिंग की तुलना में 11.5 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 9.1 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 18.7 प्रतिशत का हास हुआ।

## विदेशी ऋण

1.58 भारत का विदेशी ऋण भंडार, सितंबर-अंत 2011 को 326.6 बिलियन अमरीकी डालर पर था, जिसमें मार्चान्त 2011 में 306.4 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानों की तुलना में 20.2

बिलियन अमरीकी डालर (6.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़त प्रधानतः उच्च वाणिज्यिक उधारों और अल्पकालिक कर्ज के कारण थी। इन दोनों का मिलानुला प्रभाव देश के बाह्य कर्ज में कुल बढ़त के 80 प्रतिशत से अधिक के रूप में पड़ा।

1.59 भारत के बाह्य कर्ज के परिपक्वता अवधि विन्यास से दीर्घकालिक उधारों की प्रबलता निर्दिष्ट होती है। सितंबर 2011 के अंत में 255.1 बिलियन का दीर्घकालिक बाह्य कर्ज कुल बाह्य कर्ज के 78.1 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है जबकि शेष 21.9 प्रतिशत अल्पकालिक कर्ज था। सरकार का संपूर्ण बाह्य कर्ज 79.3 बिलियन अमरीकी डालर का था जबकि गैर सरकारी कर्ज सितंबर 2011 के अंत में 247.3 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर था। भारत का बाह्य कर्ज प्रबंधनीय सीमाओं में रहा है जैसा कि 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य कर्ज 17.8 प्रतिशत के अनुपात और कर्ज सेवा के 4.2 प्रतिशत के अनुपात से निर्दिष्ट होता है। यह सरकार की बाह्य कर्ज प्रबंधन नीति के कारण संभव हुआ है जिसमें दीर्घ और अल्पकालिक कर्ज के अनुवीक्षण, दीर्घ परिपक्वता अवधियों में रियायती शर्तों पर संपूर्ण जोखिम ऋणों के एकत्रण, अंतिम उपयोग और समग्र लागत प्रतिबंधों के ज़रिए ईसीबी के नियमन, और अनिवासी भारतीयों की जमा रकमों पर ब्याज के यौक्तीकरण पर जोर दिया गया है।

## राजकोषीय घटनाक्रम

1.60 सोद्देश्य राजकोषीय विस्तार के दो वर्षों के बाद 2010-11 के बजट में प्रेरण की आंशिक वापसी की वजह से राजकोषीय प्रवृत्तीकरण फिर से शुरू हुआ। इसका पर्याप्त परिणाम हुआ जिससे 2009-10 में राजकोषीय घाटा स०घ०उ० के 6.5 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 4.8 प्रतिशत रह गया। 2011-12 के बजट में स०घ०उ० में 4.6 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में कमी करके राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखने का प्रयास किया गया। मध्यकालिक राजकोषीय नीतिगत विवरण में निर्दिष्ट किया गया कि समष्टि आर्थिक परिणामों को बनाए रखने के लिए राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस राजकोषीय घाटे को कम करके आगे भी जारी रखा जाएगा।

1.61 आर्थिक समीक्षा में 2009-10 और 2010-11 में राष्ट्रीय लेखा आधार सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संक्रमण के दुष्प्रभाव को खत्म करने संबंधी राजकोषीय प्रोत्साहनों के समष्टि आर्थिक आयामों का विश्लेषण कुछ विस्तार से किया गया था। स०घ०उ० डाटा के हालिया परिशोधनों से जाहिर होता है कि मांग मंदन 2008-09 में तीव्रतर थी और स्थिर बाजार कीमतों पर स०घ०उ० 2008-09 में 3.9 प्रतिशत पर रहा। इसमें सकल पूंजी निर्माण में 1.6 का संकुचन और निजी अंतिम उपयोग व्यय में गिरावट शामिल थी। राजकोषीय इजाफा 2004-05 की स्थिर कीमतों के आधार पर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 10

प्रतिशत और 14 प्रतिशत तथा 2008-09 तथा 2009-10 में सरकार द्वारा किए गए पूंजी निर्माण में 12.3 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत से अधिक की हुई संवृद्धि में दिखाई पड़ा। इसके अलावा, आर्थिक सहायता रहित अप्रत्यक्ष करों में संवृद्धि 2008-09 में 14.7 प्रतिशत और 2009-10 में 10.4 प्रतिशत तक घटने के बाद 2010-11 में 28.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस इजाफे का समष्टि आर्थिक परिणाम मांग पक्ष में स०घ०उ० (स्थिर बाजार कीमतों पर) के 2008-09 में 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 8.2 प्रतिशत और 2010-11 में 9.6 प्रतिशत तक तीव्र गति से उछलने से हुआ उछाल का यह स्तर वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीव्रतम और उच्चतम था।

1.62 वैश्विक स्तर पर यह अनुस्मरणीय है कि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इस संक्रमण से निबटने के लिए अत्यल्प मौद्रिक गुंजाइश थी और उन्होंने मंदनकारी प्रवृत्तियों से उबरने के लिए राजकोषीय नीतियों का अवलंब लिया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के जनवरी 2012 के राजकोषीय अनुवीक्षण में विश्वभर में राजकोषीय इजाफा की सीमा का उल्लेख किया गया है। वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संक्रमण के दुष्प्रभाव को उपशमित करने हेतु विश्व भर में बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन के सहारे यह समग्र राजकोषीय घाटा 2008 में स०घ०उ० के 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 6.7 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2010 में स०घ०उ० के 5.5 प्रतिशत तक घटने के बाद राजकोषीय घाटे के 2011 में 4.5 प्रतिशत और 2012 में 4.1 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

1.63 सामूहिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संकट पूर्व और संकटपश्च दोनों अवधियों में बड़े पैमाने पर घाटे अद्यतन राजकोषीय अनुवीक्षण के अनुसार थे। एक ओर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का राजकोषीय घाटा 2010 में स०घ०उ० के 7.6 प्रतिशत था और उसके 2011 में 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान था, तो दूसरी ओर उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं का राजकोषीय घाटा इन दो वर्षों में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। उभरती हुई प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2010 में 8.9 प्रतिशत पर और 2011 में 8.5 प्रतिशत के अनुमानित स्तर का भारतीय राजकोषीय घाटा उच्चतम घाटा रकमों में से था। इन अनुमानों से पक्के तौर पर जाहिर है कि राजकोषीय समेकन राष्ट्रों के बीच 2010 से घटित हो रहा है। भारतीय संदर्भ में इस अनुवीक्षण का संकेत है कि प्रधान राजकोषीय संकेतकों में बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। यह औसत ब्याज दर-संवृद्धि अंतर 2011-16 की अवधि के दौरान -5.1 प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त करता है जिससे कर्ज-स०घ०उ० अनुपात के आधार पर अनुकूल गति संभव रह सकती है। भारत में 2010-11 में राजकोषीय स्थिति से इस अंतर के कारण कर्ज-स०घ०उ० के अनुपात में अनुमानित से बेहतर गिरावट की दृष्टि से अद्वितीय लाभ और अभिहित स०घ०उ० के उच्च स्तर से उत्पन्न पर्याप्त राजकोषीय सुधार अंशतः प्रतिबिम्बित हुआ। स०घ०उ० के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा

2009-10 में 6.5 प्रतिशत से गिर कर 2010-11 में 4.8 प्रतिशत पर रह गया। 2009-10 में राज्यों का राजकोषीय घाटा संघ०उ० के 2.9 प्रतिशत से 2010-11 में 2.7 प्रतिशत तक घट जाने के कारण सामान्य सरकार घाटा 2009-10 में 9.4 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में संघ०उ० का 7.9 प्रतिशत हो गया।

1.64 फरवरी 2011 में अग्रिम अनुमानों के जारी किए जाने से 2010-11 में वास्तविक संघ०उ० में संवृद्धि 9.6 प्रतिशत इंगित की गई थी, यद्यपि औद्योगिक मंदन से जुड़ी चिंता थी, फिर भी बजट 2011-12 का बजट पेश करने के समय समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में सकारात्मक और सहयोगी था। हालांकि जैसे-जैसे वर्ष बीतता गया जैसे-वैसे औद्योगिक गिरावट जारी रही और मुद्रास्फोटिकारी दबावों और मौद्रिक महंगाई से और तीव्र मांग मंदता उत्पन्न हुई। इससे लोक वित्तों पर प्रभाव पड़ने से लागतों के बढ़ने के कारण लाभ के मार्जिन फायदेमंद नहीं रहे और उससे निगमित आयकर एवं केंद्रीय उत्पाद की संवृद्धि का स्तर प्रभावित हुआ। कर वापसियों के रूप में उच्च बर्हिगमन, करेतर राजस्वों के स्तरों, और इक्विटी बाजार की स्थिति जो वर्तमान राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में नियोजित विनिवेश प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त थी, से वर्तमान राजकोषीय वर्ष में बजटीकृत राजस्वों के अर्जन का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। वैश्विक कच्चे पेट्रोलियम की कीमतें ऊंची बनी रहीं और, घरेलू कीमत नियतन में खास सीमित नम्यता के चलते कुछ अतिरिक्त व्यय किया गया है जिसके निहितार्थ राजस्व और राजकोष दोनों घाटों के स्तरों के लिए है। यह अप्रैल-दिसंबर 2011 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए केंद्रीय लेखा के डाटा में प्रतिबिम्बित है।

1.65 केंद्रीय लोक वित्त अप्रैल-दिसंबर 2011 में बजट अनुमान के 93.1 प्रतिशत पर राजस्व घाटे और 92.3 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे के रहने कारण कुछ दबाव में प्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। प्रथम नौ महीनों में सकल कर राजस्व ऐसी दर पर बढ़ गया है। जो 2010-11 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में ब०अ० 2011-12 में परिकल्पित वर्षानुवर्ष संवृद्धि से 5 प्रतिशत बिंदु अल्पतर है। ऐसा ब०अ० 2011-12 द्वारा परिकल्पित 20.2 प्रतिशत के मुकाबले में 6 प्रतिशत पर निगम कर में अल्पवृद्धि के कारण प्रधानतः और इस वर्ष की वापसियों के उच्च स्तरों और उत्पाद शुल्कों में बजटीकृत से काफी अल्पतर संवृद्धि के कारण अंशतः हुआ है। यह मानते हुए कि 2010-11 में व्यय में पर्याप्त बढ़त रही, जो करेतर राजस्वों में अनुमानित से अधिक प्राप्तियों से बढ़े पैमाने पर संभव हुई, 2011-12 के बजट में पूरे वर्ष के कुल व्यय के लिए 4.9 प्रतिशत का संवृद्धि लक्ष्य अनुमानित किया गया था। 2011-12 के प्रथम नौ महीनों में कुल व्यय में संवृद्धि 13.9 प्रतिशत थी, जिसमें आयोजना भिन्न व्यय में 15.4 प्रतिशत की संवृद्धि और

आयोजना व्यय में 10.8 प्रतिशत की संवृद्धि शामिल थी। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के लिए बजटीकृत राजस्व और राजकोषीय घाटे से कभी संभावना इसे न्यूनतम करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद रहती है।

1.66 2008-09 और 2009-10 में राज्यों (सम्मिलित) की राजकोषीय स्थिति संघ०उ० के 3.0 प्रतिशत से अल्प राजकोषीय घाटे और राजस्व अधिशेष एवं राजस्व घाटे के परिमित स्तरों के कारण काफी बेहतर थी। यह वर्ष 2008-09 और 2009-10 में कर राजस्व में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष संवृद्धि से संभव हुआ था। इसमें 2008-09 तथा 2009-10 में क्रमशः राज्यों के निजी करों में 12.3 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत बढ़त तथा केंद्र से अंतरित करों में 5.5 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत बढ़त शामिल थी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के लिए उपचित हो रहे अनुदानों के उच्च स्तरों के कारण उनकी राजस्व प्राप्तियां (सम्मिलित) 2008-09 में संघ०उ० के 12.3 प्रतिशत पर निर्धारित हुईं। 2008-09 और 2009-10 के संक्रमण प्रभावित वर्षों में भी मंद रहने के बाद कुल व्यय में वृद्धि 2010-11 में 22.1 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। संघ०उ० के अनुपात के रूप में राज्यों का कुल व्यय 16.1 प्रतिशत पर था। कुल व्यय के इस स्तर पर रहने के बाद भी राजस्व और राजकोषीय घाटे 2011 में संघ०उ० के क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत पर रखे गए। ब०अ० 2011-12 में राज्यों के राजकोषीय घाटे के संघ०उ० के 2.2 प्रतिशत तक गिरने एवं राजस्व अधिशेष के संघ०उ० के 0.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

1.67 मध्य वर्ष विश्लेषण 2011 में यह सारगर्भित रूप से इंगित किया गया था कि राजकोषीय नीतियों के समष्टि आर्थिक आयामों को समेकित सामान्य निधि के स्तर पर राजकोषीय समुच्चयों के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। समेकित सामान्य सरकार के घाटों के अर्थ में वास्तविक परिणाम उस परिणाम की तुलना में कहीं बेहतर रहा है जिसका विशिष्ट निर्धारण वर्ष के दौरान किया गया है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के संकट प्रभावित वर्षों में यह बढ़ गया था किन्तु 2010-11 में गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.9 प्रतिशत रह गया और वर्ष 2011-12 में इसके सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस वर्ष केन्द्र के राजकोषीय परिणाम में संभावित कमी से समेकित सरकारी घाटा बढ़ सकता है, फिर भी यह संतुलित हो सकता है यदि राज्य बेहतर निष्पादन करना जारी रखे। यह अनिवार्यतः एक अपवादात्मक वर्ष है जब सम्पूर्ण कारक बजट के प्रस्तुतीकरण के समय यथा परिकल्पित से भिन्नतः उभरे हैं। संभावित विचलन (क्रमशः विगत तथा वर्तमान राजकोषीय वर्ष में) द्वारा अनुसरित एक बड़ा राजकोषीय

सुधार कुछ-कुछ एक चक्रीय राजकोषीय समायोजन के स्वरूप का है किन्तु आगे बढ़ते हुए राजकोषीय समेकन के एक मध्यावधि ढांचे में सुव्यवस्थित होने की संभावना है जो ऐसे जोखिमों को कम करता है।

## मानव विकास

1.68 भारत अप्रत्याशित जनसांख्यिकी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। यह 'जनसांख्यिकी लाभांश' जहां भारत को अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध कराता है वहीं एक बड़ी चुनौती भी प्रस्तुत करता है। भारत को अभी भी मानव विकास संकेतकों, विशेषतया स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में मानव विकास संकेतकों के अर्थ में अभी काफी दूरी तय करनी है। तथापि, बेहतर निष्पादन करने की महत्ता को अनदेखा किए बिना यह उल्लेखनीय है कि 1980-2011 के दौरान प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि एचडीआई रैंकिंग में पिछड़ेपन के बावजूद औसत वार्षिक एचडीआई विकास दर के संदर्भ में भारत ने अधिकांश देशों से बेहतर निष्पादन किया है।

### भारत के सामाजिक क्षेत्र की व्यय परक प्रवृत्तियां

1.69 सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय (योजना और गैर-योजना) वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ा है। वर्ष 2006-07 में केन्द्र सरकार के कुल 13.38% व्यय से बढ़कर वर्ष 2011-12 में यह 18.47% हो गया। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता लगातार बढ़ती रही जबकि अधिकांश सामाजिक क्षेत्रगत विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2006-07 में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 24.1% हो गया और बाद में वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में 25% हो गया। जीडीपी के संदर्भ में यह हिस्सा वर्ष 2006-07 में 5.57% से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 7.34% हो गया। इससे भारत सामाजिक क्षेत्र पर अधिक विपरीत प्रभाव के बिना वैश्विक संकट का सामना कर सका। वर्ष 2011-12 में बजट अनुमान के अनुसार यह 6.74% होने का अनुमान है। जीडीपी के अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय वर्ष 2006-07 में 2.72% से 2011-12 (ब.अ.) में 3.11% तक बढ़ा; स्वास्थ्य पर व्यय वर्ष 2006-07 में 1.25% से वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में 1.30% तक बढ़ा। ये कार्यक्रम जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतरी में भी भूमिका अदा करते हैं, साथ ही और अधिक समावेशी विकास में योगदान देते हैं।

### रोजगार

1.70 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था एनएसएसओ पंचवर्षीय सर्वेक्षण ने वर्तमान दैनिक स्थिति (सीडीएस) 2004-05 तथा 2009-10 के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों में 18 मिलियन

तक की वृद्धि की सूचना दी है। तथापि समग्र श्रम शक्ति केवल 11.7 मिलियन बढ़ी। पहले की अवधियों की तुलना में यह पर्याप्त कम थी जिसका कारण युवाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवधारण और कार्यशील (वर्किंग) आयु की महिलाओं की श्रम शक्ति में अपेक्षाकृत कम भागीदारी का होना था। पूर्ण संभाव्यता के साथ यह बेहतर आर्थिक दशाओं का संकेतक है। परिणामतः बेरोजगारी वास्तविक रूप में 6.3 मिलियन कम हुई। श्रम शक्ति में कम वृद्धि जारी रहने का अनुमान नहीं है क्योंकि शिक्षित युवाओं के 12वीं योजना और आगे के वर्षों में बढ़ी संख्या में कार्यभार ग्रहण करने का अनुमान है। इसका तात्पर्य यह है कि रोजगार/जीविका के अवसरों में वृद्धि की गति तेज होनी है 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसे समग्र उत्पादन में प्रभावित और श्रम शक्ति के योगदान में सुधार के एक साधन के रूप में भी माना जा सकता है।

1.71 वर्ष 2009-10 में बेरोजगारी के विभिन्न अनुमानों के बीच तुलना से पता चलता है कि बेरोजगारी का सीडीएस अनुमान सबसे अधिक (सारणी 1.8) है। सीडीएस दृष्टिकोण के अनुसार साप्ताहिक स्थिति एवं सामान्य स्थिति की तुलना में उच्च बेरोजगारी की दरों में विरामी बेरोजगारी की ऊंची डिग्री का पता चलता है। रोचक तौर पर यूसुअल प्रिंसिपल एण्ड सबसिडियरी स्टेटस (यूपीएसएस) तथा करेंट वीकली स्टेटस (वर्तमान साप्ताहिक) (सीडब्ल्यूएस) दोनों के अंतर्गत शहरी बेरोजगारी अधिक थी लेकिन सीडीएस के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगारी अधिक थी। तथापि, 2004-05 की तुलना में प्रत्येक पैमाने पर बेरोजगारी की समग्र दर कम थी।

1.72 तिमाही समीक्षा रिपोर्टों (जुलाई से सितम्बर 2011) के अनुसार 2010-11 में रोजगार की स्थिति से पता चलता है कि जुलाई 2009 से रोजगार सृजन में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को बनाए रखा गया है। चुनिंदा क्षेत्रों अर्थात् टेक्सटाइल्स, जिसमें परिधान, लेदर, मेटल्स, आटोमोबाइल, जेम्स एवं जूलरी, परिवहन; सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग (बीपीओ) और हैंडलूम/पावरलूम शामिल हैं, से पता चलता है कि सितम्बर 2011 में समग्र रोजगार सितम्बर 2010 की तुलना में 9.11 लाख तक बढ़ा। आईटी/बीपीओ सेक्टर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई (7.96 लाख),

**सारणी 1.8 : अखिल भारत एनएसएस 66वें दौर शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की दरें**

क्रम सं.	अनुमान	ग्रामीण 2009-10	शहरी 2009-10	कुल 2009-10	कुल 2004-05
1	यूपीएसएस	1.6	3.4	2.0	2.3
2	सीडब्ल्यूएस	3.3	4.2	3.6	4.4
3	सीडीएस	6.8	5.8	6.6	8.2

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन



धातु में (1.07 लाख), आटोमोबाइल में (0.71 लाख) जेम्स और जूलरी में 0.08 लाख और चमड़ा उद्योगों में (0.07 लाख)।

## यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इण्डिया (यू आई डी ए आई)

1.73 यूनिक आईडेंटिफिकेशन (यूआईडी) परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है और लगभग 13 करोड़ आधार नम्बर (यूआईडी नम्बर) पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। आधार नम्बर को नए एलपीजी कनेक्शनों के लिए पहचान पते का मान्य प्रमाण माना गया है। इससे सरकारी विभागों द्वारा कल्याणकारी निधियों के वितरण की प्रक्रिया पर्याप्त आसानी होगी।

## सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन

1.74 विशेषकर कम आय वाले देशों में सतत् विकास एक कठिन कार्य है। समाज को साथ-साथ तीन बातों का प्रतिपादन करना होगा: वर्तमान पीढ़ी के लिए सामाजिक-आय के आर्थिक स्तर में सुधार; भूमि, हवा, वन, ऊर्जा एवं जल संसाधनों का उपयोग और अधिक प्रतिबंधित तरीके से करना तथा भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना। विकासशील देशों में विकल्पों को तरजीह देना और अधिक कठिन है क्योंकि वे व्यक्तियों की जीविका को प्रभावित करते हैं। ऐसे 'प्रबन्धन' की सफलता के लिए लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, पसंद और लागत के आधार पर सूचना का आदान प्रदान करना होगा तथा भागीदारी और स्वामित्व को निश्चित करना होगा। आशा है कि इस बात को जून 2012 में रियो में द्वितीय अर्थ शिखर सम्मेलन में केन्द्रीय स्तर पर रखा जाएगा, जिसमें वैश्विक सतत् विकास प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा।

1.75 भारत ने विगत के दशकों में प्रबन्धन में बेहतर परिणाम दिए हैं। इसने मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों के सन्दर्भ में सजगता से अनुसरण किया है। पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सतत् विकास भारतीय नीति एवं आयोजना की विषय-वस्तु रहा है। 1980 से आर्थिक सुधारों ने विकास एवं आय में बढ़ोत्तरी को गति प्रदान की है। जीवन की अपेक्षाओं और अन्य संकेतकों के पैमाने पर सामाजिक स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। भारत ने अपने वन जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को आगे बढ़ाया है। भारत के विकास मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रही सेवाओं पर भरोसा किया गया है, जिससे विकास मार्ग में उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में मदद मिली है तथा साक्षरता एवं शिक्षा में तेजी आई है। भारत ने काफी

कुछ किया है लेकिन और बेहतर परिणाम दिए जा सकते थे। ऐसी प्रगति के पीछे निहित कारण है असंदिग्ध सुदृढ़ संस्थाएं; प्रजातांत्रिक भागीदारी, सामाजिक न्याय की संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरणीय कानून एवं नियमों, बहुकर्ताओं, बाजारों और विकासशील सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों पर दृढ़ आस्था।

1.76 तथापि बड़ी चुनौतियां सामने हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण रिपोर्ट 2009 में भारत द्वारा अनुभव की जा रही पांच प्रमुख चुनौतियों अर्थात् जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा एवं शहरीकरण के प्रबंधन को एक साथ जोड़ा गया है। पर्यावरणीय स्थायित्व के लिए व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास जरूरी है। ऊर्जा एवं अन्य ससाधनों की कम कीमत से हम और अधिक सतत् विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। उपयुक्त, प्रौद्योगिकियों का प्रसार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही गरीबों के लिए ऊर्जा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु खर्च को बढ़ाना होगा।

1.77 जलवायु परिवर्तन की चुनौती घरेलू और राष्ट्रीय स्तरों पर राजनैतिक नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। जलवायु में परिवर्तन के लिए मुख्यतः वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन के साथ बाढ़, सूखा, की घटनाओं की तीव्रता में और अधिक बढ़ोत्तरी की अनुमान है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से परिस्थितिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव का पता चलता है जबकि बेतरतीब आर्थिक विकास के कारण ये पहले से ही दबाव में हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर नीतियों एवं संसाधनों की दृष्टि से ध्यान दिए जाने योग्य प्रमुख चुनौती है।

1.78 जलवायु परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क संघ (यू एन एफ सी सी, संघ) का 1992 में गठन किया गया था और 1994 में इसने कार्य करना शुरू किया। यद्यपि वैश्विक रूप से संबंधित क्षमताओं, आर्थिक ढांचों, संसाधन आधार और इक्विटी के सिद्धान्त के आधार पर, जो जलवायु परिवर्तन, संबंधी बहस के केन्द्र में है, पार्टियों की प्रतिबद्धताओं/उत्तरदायित्वों में मत भिन्नता रही। संघ विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण करता है। यह मानता है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन विकास शील देशों की पहली और मूलभूत प्राथमिकता है।

1.79 जलवायु परिवर्तन वित्त के संदर्भ में बड़े निहितार्थों वाला जटिल नीतिगत मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु सभी

कार्यों पर अंततः लागत अंतर्विष्ट है। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन और प्रशमन की योजनाएं और परियोजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करने के लिए निधिपोषण महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों द्वारा अपने घरेलू प्रशमन और अनुकूलन कार्य बढ़ाने हेतु अपेक्षित वित्तीय सहायता के मापदंड और मात्रा यूएलएफसीसीसी के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में अत्यधिक बहस के मामले हैं। अभिसमय विकसित देशों द्वारा वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के स्टाक में योगदान को देखते हुए वित्तीय सहायता की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से उन पर डालता है। इस कार्य के महत्व और आवश्यक निधियों को देखते हुए घरेलू वित्तपोषण संभवतः विकासशील देशों की चालू और अनुमानित जरूरतों के लिए कम पड़ जायेगा। अभिसमय के बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से वैश्विक निधियन प्रशमन प्रयासों के वित्तपोषण की घरेलू क्षमता बढ़ाएगा।

1.80 हाल ही में 28 नवंबर से 10 दिसंबर, 2011 तक आयोजित डर्बन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में महत्वपूर्ण अगला कदम माना गया है (ब्यौरे के लिए अध्याय 12 का बाक्स 12.6 देखें)। डर्बन के परिणामों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है क्योंकि उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी वचनबद्धता अवधि की व्यवस्था की और ग्रीन जलवायु निधि (जीसीएफ), प्रौद्योगिक तंत्र (टीएम) और अनुकूलन ढांचे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कैनकुन करारों को प्रचालनरत किया। डर्बन के परिणामों ने, उस वैश्विक जलवायु परिवर्तन व्यवस्था जिसके लिए डर्बन मंच शुरु किया गया है, 2020 के बाद की व्यवस्थाओं संबंधी विचार विमर्शों के लिए एक स्थल भी खोला है। यद्यपि भारत और अन्य विकासशील देश डर्बन में जबरदस्त दबाव में आ गए परन्तु भारत यह सुनिश्चित करने के लिए आगे रहा कि अभिसमय में नई व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से स्थिर की गई हैं और ये 'सामान्य परन्तु विभेदक उत्तरदायित्वों और इक्विटी' के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

### अल्पावधिक और मध्यावधिक परिदृश्य

1.81 यूरोप में वित्तीय संकट के साथ जापानी परमाणु आपदा जैसे कुछ बहिर्जात झटकों के परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान तीव्र वैश्विक आर्थिक मंदी आई है। जब यह एक मंदी-पिछली मंदी 2008-09 में आई थी—के बाद इतनी जल्दी घटित हो, तो इससे निपटना आसान नहीं है। अधिकतर मानक और सुविज्ञ नीतियां पहले ही पूर्ण: क्षमता के अनुसार प्रयोग की जाती है और पुनः प्रयास निष्फल हो सकते हैं। समूचा विश्व, विशेषकर यूरोप सावधानी से कदम रख रहा है और वर्तमान समस्याओं के नए इलाज ढूँढने के लिए कार्य कर रहा है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत की विशिष्ट वृद्धि और विश्व के साथ बढ़ते हुए समेकन के कारण यह वैश्विक घटनाक्रमों से ज्यादा समय तक अप्रभावित नहीं

रह सकता। आश्चर्य की बात नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है और इसकी सकल घरेलू वृद्धि संभवतः चालू वर्ष के दौरान गिरकर 6.9 प्रतिशत होने की संभावना है। यह वही दर्शाता है जो 2008-09 में हुआ था जब वृद्धि 6.7 प्रतिशत हुई थी और दबाव राष्ट्र पर है कि वृद्धि के पुनरुज्जीवन के लिए नीतियों में सुधार करे।

1.82 इसमें कोई शक नहीं कि भारत की मंदी का एक हिस्सा घरेलू कारणों में छिपा है। निरंतर मुद्रास्फीति जो वर्ष के अधिकतर समय 9 प्रतिशत से ऊपर बनी रही है और इसे ठीक करने की जरूरत है, इसने एक भूमिका निभाई है। स्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति कठोर बनानी पड़ी जिसने उधार की लागत बढ़ा दी और इसने उद्योग में वृद्धि को प्रभावित किया। लोकतांत्रिक राजनीति के दबाव भी थे जिन्होंने सुधारों को मंदा कर दिया था। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए यह युक्तिसंगत जान पड़ता है कि इस वर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के 6.9 प्रतिशत के अग्रिम अनुमान को पृष्ठांकित किया जाए। अनेक सांख्यिकीय संकेतकों के मार्ग पर आधारित आकलनों और पूंजी-उत्पादन अनुपातों के अनुमान हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं कि 2012-13 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6 (+/-0.25) प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की जा सकती है।

1.83 सुधार के आरम्भतः मंद होने का मुख्य कारण निवेश दर में मामूली गिरावट का होना है। 2011-12 की तीसरी तिमाही में सकल नियत पूंजी निर्माण एक वर्ष पूर्व के 32.3 प्रतिशत से कम होकर 30 प्रतिशत थी। किन्तु राजकोषीय समेकन के ट्रैक पर आने से बचत तथा पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में मुद्रास्फीतिकारी दबावों के कम होने से आरबीआई द्वारा नीति दरों में कमी की जा सकती है जिससे वृद्धि दर सकारात्मक प्रभाव वाले निवेश क्रियाकलाप को अभिप्रेरित करने वाली होगी। ये कारक इस तथ्य के साथ कि 35.1 प्रतिशत पर भारत की निवेश दर अभी भी प्रभावशाली है, वर्ष 2011-12 में 2012-13 में वृद्धि में मजबूती में परिणामी होने चाहिए और इसके बाद इसमें और तेजी आनी चाहिए। आरम्भिक आकलन इंगित करते हैं कि 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत होगी। वास्तव में दीर्घावधिक पूर्वानुमान त्रुटि के बड़े अंतर के साथ आते हैं। ये अनुमान सामान्य मानसून, यौक्तिक रूप से स्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें विशेषतया तेल की कीमतें और वैश्विक वृद्धि जो अब है उसके आसपास और 0.5 प्रतिशत अधिक जैसे कारकों संबंधी मान्यताओं पर आधारित है। इन स्थितियों से विपथन होने पर भारत के वृद्धि पथ पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, 15 वर्ष की उत्कृष्ट वृद्धि और लगभग एक दशक से 30 प्रतिशत की



अधिक की निवेश दर के कारण अब अर्थव्यवस्था में हमारे लिए पर्याप्त लोचशीलता इतना आशावादी होने की है कि भारत वैश्विक वृद्धि का अग्रणी ईजन हो सकता है।

1.84 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वृद्धि 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम रही है जो विगत योजना अवधियों की तुलना में स्पष्ट सुधार के बावजूद है। यद्यपि कृषि अब 13.9 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर सिकुड़ गई जैसाकि एक वृद्धिकारी अर्थव्यवस्था से आधा की जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए आजीविका प्रदाता है। यह क्षेत्र कैसा निष्पादन करता है इसका भी समग्र मूल्यां पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए यह वह क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र पिछले तीन दशकों में कम हुआ है। यही अपने आप में चिंता की बात नहीं है बल्कि चिंता की बात भारतीय कृषि की कम उत्पादकता का होना है। उत्पादन के मापदंडों में भारत अधिकतर फसलों में वैश्विक स्तरों से पिछड़ा हुआ है। सम्मिलित और केंद्रित प्रयास कृषि में अवरोधित उत्पादकता की चुनौती के समाधान के लिए अपेक्षित हैं। कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी एक साथ कार्यक्रम का अच्छा दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का प्रसार और गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसी कृषीय निविष्टियों की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण होगा। इससे भी बढ़कर, कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। विशेष रूप से उद्यान कृषि, मात्स्यकी, पशुपालन, मुर्गीपालन तथा संबंधित क्रियाकलापों को इन क्षेत्रों में निजी तथा मात्स्यकी दोनों क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर संबर्धित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जलसंभर, कंटूर बंधन तथा जल संग्रहण संरचनाओं में उच्चतर निवेश आवश्यक होगा। इनमें से कुछ क्रियाकलाप एमएनईआरजी के तहत किए जा सकते हैं।

1.85 यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि उत्पादकता को स्वयं ही प्रोत्साहन मिलेगा यदि खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति की कड़ी को सुधारा जाए। इससे किसानों को अपने उत्पादों के अच्छे मूल्य मिलेंगे और उन्हें निवेश करने व उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सुधरी हुई आपूर्ति कड़ी का रहस्य सरकार के पास नहीं है कि वह अपने प्रशासन और अधिकारी वर्ग का प्रयोग करते हुए इसकी सीधे व्यवस्था करे बल्कि नीतिगत उपाय करे जो निजी भागीदारी को यह महत्वपूर्ण सेवा देना सुसाध्य बनाए। 'इन सुसाध्यकारी नीतियों में साधारणतया ये शामिल हैं नियमों में बदलाव करना ताकि व्यष्टियों और फर्मों को इस व्यवसाय में उतरने की अनुमति दी जा सके और अपने विनियमों को साफ किया जाए ताकि लोगों को व्यवसाय व व्यापार के प्रत्येक समय अनावश्यक रूप से अनुमति न लेनी पड़े। यह प्रसंग सर्वेक्षण में बाद में फिर आएगा।

1.86 औद्योगिक क्षेत्र ने इस वर्ष कमजोर निष्पादन किया है और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा जो 28.7 प्रतिशत के शिखर पर था अब गिरकर 27 प्रतिशत हो गया है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल घटना है। यह संभावना है कि यह गिरावट 2012-13 में शुरू होकर अपने आप वापस पलट जाएगी। यद्यपि, उद्योग उभरती हुई अर्थव्यवस्था की वृद्धि का ऐसा महत्वपूर्ण चालक और रोजगार प्रदाता है कि इस क्षेत्र को इस वर्ष की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। एक सरल सा इशारा इस तथ्य में मिलता है कि भारतीय सेवाएं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं ने पिछले दो दशक में बहुत अच्छा कार्य किया है और सेवा क्षेत्र मोटे तौर पर कर संजाल के बाहर होने के चलते राज्य की मशीनरी के ज्यादा संपर्क में नहीं रहना पड़ता और इस पर अवसंरचनात्मक अवरोधों का भी कम प्रभाव पड़ा था क्योंकि कई सेवाओं को माल भाड़ों और पत्तनों की जरूरत नहीं होती है। यह सुझाता है कि हम विनिर्माण और उद्योग की जो बड़ी मदद कर सकते हैं वह है अपनी अवसंरचना को सुधारना और प्रशासन से कम से कम संपर्क करने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र इतना मजबूत है कि यह अपने आप चलने लगेगा; हमें बस व्यवसाय में समर्थ बनाने का माहौल देने की जरूरत है। इस संबंध में विनिर्माण के लिए प्रथम समर्पित नीतिगत उपाय के रूप में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणा देने की आशा है। श्रम कल्याण तथा पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े मुद्दों का निवारण करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति व्यवसाय विनियमों का सरलीकरण करने तथा उद्योग के लिए लेन देन लागतें कम करने का प्रयत्न करने और इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है।

1.87 वर्ष 2010-11 और 2011-12 में सेवा वृद्धि में मामूली कमी आई है। यह मुख्यतः सरकारी प्रशासन और रक्षा सेवाओं की वृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण हुआ है जिसने सरकार के लिए कुछ राजकोषीय स्थान बनाया है। व्यापार, होटल और रेस्तरां में वृद्धि 11.2 प्रतिशत पर ज्यादा सुदृढ़ है। यदि ब्याज दरें ऊंची बनी रही तो स्थावर संपदा, आश्रयों के स्वामित्व और व्यवसाय सेवाओं में, जिनमें मंदी आनी शुरू हो गई है, वृद्धि के बारे में कुछ चिंता होगी। अर्थव्यवस्था में कुछ सेवाओं का दृष्टिकोण वैश्विक परिदृश्य से भी जुड़ा है। जबकि सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात एक समान बने हुए हैं यूरो क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के कारण इस क्षेत्र में कुछ सुस्ती रह सकती है। अच्छी-मौसमी व्यवसाय सेवाओं में वृद्धि जिसने पहले ही मंदी के लक्षण दिखा दिए हैं, उसमें संभवतः बेहतर न आए। अन्य दो प्रमुख सेवाओं में परिवहन पहले ही अब तक के निम्न बाल्टिक ड्राई सूचकांक से प्रभावित हो चुका है यद्यपि यह अस्थायी स्वरूप का हो सकता है। हालांकि, यात्रा और पर्यटन भी

प्रभावित हो सकते हैं, इससे पर्यटक अंतर्वाह पद्धति में बदलाव भी आ सकता है, ऐसा भारत जैसे सस्ते गंतव्यों को खोजने वाले हालीडे बैंकपैकर्स के वर्द्धित अंतर्वाह के कारण हो सकता है। दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि इस क्षेत्र में और सहायक हो सकती है।

1.88 मार्च 2010 से नीतिगत दरों में 13 समायोजनों सहित मौद्रिक नीति का फोकस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीतिकारी अनुमानों को स्थिर रखने पर रहा। इससे प्रत्याशा के अनुरूप विकास की गति को मंद करने का अल्पावधिक प्रभाव रहा। लेकिन इसने मुद्रास्फीति को मार्च तक 6.5% के आसपास संतुलित बनाए रखने में भी योगदान दिया। इसके बावजूद, इसपर नज़र रखे जाना अपेक्षित होगा और अप्रत्याशित घटनाओं तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि जैसे वैश्विक आघातों से निपटने के लिए शीघ्र ही अपेक्षित उपायों की आवश्यकता होगी।

1.89 यूरोप के बैंकों के लिए अभी हाल ही में नियामक नुस्खों से शक्ति हास का भय सामने आया है। संकटग्रस्त अंचलों की ओर

उनके नाममात्र के एक्सपोजर के कारण भारतीय बैंकों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि, वित्त पोषण संबंधी दबावों के कारण अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं। संचित वित्तीय जोखिमों के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के क्रम में वित्तीय नियमों में काउन्टर साईक्लिकल वित्तीय नीति की संभावनाओं का पता लगाया जा सकेगा। इससे वित्तीय प्रणाली को आवश्यक स्थिरता प्रदान करने में अभी काफी समय लगेगा।

1.90 जैसाकि पहले ही संकेत दिया गया है कि केन्द्र के सन्दर्भ में इस वर्ष राजकोषीय परिणाम में स्लिपेज की संभावना है। तथापि राज्यों के ट्रेक पर रहने की संभावना है; अनुमान से अपेक्षाकृत कम राजकोषीय परिणाम से अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत और अपर्याप्त राजस्व उत्पादन के बारे में अनुमान जोखिम भरे होने का पता लगता है। आगे, राजकोष का समन्वय कुछ इस प्रकार करना होगा कि वह कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि जैसे जोखिमों को वहन कर सके और अगले अध्याय में इस बारे में विकल्पों के ब्यौरे दिए गए हैं जो कि वांछनीय वृहद् आर्थिक परिणामों के लिए आवश्यक सूक्ष्म आधारभूत सुधार हैं।